राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण रविवार,०९ मई २०२१ वर्ष-४, अंक -१०५ पृष्ठ-०८ मूल्य-०१रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

वैक्सीन की कमी से 18+ वालों का बढ़ेगा इंतजार, महाराष्ट्र में अब इस एज ग्रुप वाले लोगों को पहले टीका देने पर विचार

मुंबई। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में देशभर में 1 मई से ही वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का आगाज हो चुका है, मगर कई राज्यों में अब भी टीकों की कमी की वजह से 18 से 44 साल के उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया है। 18 से 44 साल के बीच वाले लोगों के लिए वैक्सीन की किल्लतों से जूझ रहा महाराष्ट्र अब एक अलग प्रायोरिटी ग्रुप को पहले वैक्सीन देने पर विचार कर रहा है। शुक्रवार को सरकार ने इशारा किया कि टीकों की कमी और टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ रही भीड़ को कंट्रोल करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार अब सबसे पहले 35 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देने पर विचार कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश तोपे ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द ही इस पर फैसला ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 18-34 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन तब लगेगी, जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। टोपे ने कहा कि यह यह कदम तब उठाया गया है, जब हमने ऐसे कई उदाहरण देखे, जहां शहरी क्षेत्रों के लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्रों पर अप्वाइंटमेंट ले रखी है। बता दें कि फिलहाल, राज्य में 18-44 आयु वर्ग के नागरिकों को एक जिले में केवल पांच केंद्रों पर वैक्सीन दी जा रही है, क्योंकि खुराक की संख्या सीमित है। राज्य ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत 300,000 कोविशील्ड डोज के साथ शुरू की और बाद में कोवैक्सिन की 479,000 खुराक खरीदी। महाराष्ट्र में 1 मई से अब तक 18-44 श्रेणी में 215,284 नागरिकों को टीका लगाया गया है। मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के बीच अशांति का कारण बनती हैं। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर शहरों के तकनीक-प्रेमी लोग तालुका और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए तारीखें ले ले रहे हैं।

कैसे जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बढ़ती ही जा रही तल्खी

नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगातार भयावह होती स्थिति के बीच केंद्र सरकार व कई विपक्ष शासित राज्यों में समन्वय की कमी भी साफ खटक रही है। इन राज्यों खासकर विपक्ष शासित और केंद्र के बीच तालमेल न होने से चिकित्सीय सुविधाओं के लिए जद्दोजहद बढ़ी है और एक समग्र नीति पर काम करना मुश्किल लग रहा है। इससे राजनीतिक तल्खी भी बढ़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष शासित राज्य केंद्र को घेरने में कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते हैं। गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल को लेकर उनपर कटाक्ष किया। लेकिन इसके पहले भी कई अन्य घटनाएं टकराव की ओर साफ इशारा करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बैठक का लाइव प्रसारण करने को लेकर तल्खी नजर आई थी। प्रधानमंत्री की आपत्ति पर केजरीवाल ने खेद जता दिया था। लेकिन ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य पटरी पर नजर नहीं आये। अंततः कोर्ट को दखल देना पड़ा। उधर कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उद्धव ठाकरे द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री को किये गए फोन कॉल पर जवाब न मिलने का आरोप लगाया था। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्य टीकाकरण को लेकर केंद्र को लगातार घेर रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कोविड की भयावह स्थिति के मद्देनजर प्रधानमंत्री खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वे लगातार बैठकें कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि जिम्मेदारियां एक-दूसरे पर डालने की कोशिश हो रही हैं। इतना हीं नहीं, विदेशों से बड़ी संख्या में मदद स्थिति को संभालने के लिये मंगाई गई है। लेकिन राज्य इस मदद के समान वितरण को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं।

कोरोना की भयावह स्थिति पर प्रधानमंत्री की नजर

सूत्रों का कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कोविड की भयावह स्थिति के मद्देनजर प्रधानमंत्री खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वे लगातार बैठकें कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि जिम्मेदारियां एक-दूसरे पर डालने की कोशिश हो रही हैं। इतना हीं नहीं, विदेशों से बड़ी संख्या में मदद स्थिति को संभालने के लिये मंगाई गई है। लेकिन राज्य इस मदद के समान वितरण को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं।

कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर भी असर

सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार के सामने कोविड संकट पर नियंत्रण की चुनौती है। क्योंकि इससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है। साथ ही इस संकट का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। विदेशी मदद और देश में चल रहे प्रयास से स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि राज्यों में भरोसा पैदा करने के लिए केंद्र सरकार को कोविड की पहली लहर के दौरान अपनाई गई समग्र रणनीति अपनानी पड़ सकती है। जानकारों का कहना है कि कोविड संकट से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र का सहयोग चाहिए। राज्यों को भी केंद्र द्वारा सुझाये गए मॉडल और उपायों की अनदेखी नही करनी चाहिए। क्योंकि ये राष्ट्रीय संकट है।

कोरोना कहर को रोकने के लिए तमिलनाडु में 10 से 24 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए राज्य में 10 मई से अगले दो सप्ताह तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। यानी तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस बात की जानकारी एक आधिकारिक बयान में दिया गया है। बता दें कि तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बयान में कहा कि जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक में मिले इनपुट के आधार पर यह लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 मई को सुबह चार बजे से 24 मई सुबह चार बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को ही छूट मिलेगी। तमिलनाडु में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 26,465 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 13,23,965 हो गई। बीते 24 घंटे में 197 रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 15,171 तक पहुंच गई है। शुक्रवार को 22,381 लोगों को छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब उपचाराधीन रोगियों की संख्या 1,35,355 है। चेन्नई में संक्रमण के 6,738 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,77,042 हो गई है। अब तक 5,081 रोगियों की मौत हो चुकी है।

केरल में आज से लॉकडाउन

कोरोना के बढ़त मामलों पर काबू पाने के उद्देश्य से आज से केरल में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। केरल में 8 मई सुबह 6 बजे से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को ही छूट मिलेगी।बता दें कि केरल में कोरोना अब रिकॉर्ड बनाता जा रहा है।

उखड़ती सांसों के लिए कुवैत समेत कई देशों ने भेजी सहायता

मुश्किलें कम करने को वायुसेना और नौसेना ने भी झोंकी ताकत

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण से पैदा मुश्किल के वक्त में खाड़ी के नन्हें मित्र देश कुवैत ने भारत को 215 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल आक्सीजन और 2,600 आक्सीजन सिलेंडर भेजे हैं। नई दिल्ली स्थित कुवैती दूतावास ने कहा है कि जल्द 1,400 मीट्रिक टन गैस और भेजी जाएगी। इधर भारतीय वायुसेना राहत पहुंचाने वाले प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हाल के दिनों में वायुसेना ने सात देशों के लिए 59 उड़ान भरकर 72 क्रायोजेनिक आक्सीजन स्टोरेज कंटेनर और 1,252 आक्सीजन सिलेंडर एकत्रित किए। जिन देशों से यह सामग्री लाई गई, वे हैं- सिंगापुर, दुबई, थाइलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और आस्ट्रेलिया।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार वायुसेना के सी-17 विमानों ने देश के भीतर भी 400 उड़ानें भरकर आक्सीजन और चिकित्सा के लिए आवश्यक अन्य सामग्री की आपूर्ति की। इसके अतिरिक्त नौसेना ने भी तटवर्ती इलाकों में

अपनी कोशिशों से आक्सीजन सिलेंडर और अन्य चिकित्सा उपकरण पहुंचाकर नागरिक प्रशासन की मदद की।

नौसेना के युद्धपोत आइएनएस तलवार, आइएनएस कोलकाता, आइएनएस ऐरावत, आइएनएस कोच्चि, आइएनएस तबर, आइएनएस त्रिकंड, आइएनएस जलश्व और आइएनएस शार्दुल ने आक्सीजन और उससे जुड़ा जरूरी सामान मित्र देशों से लाने और उनकी देश में आपूर्ति का कार्य किया। नौसेना ने अहमदाबाद में धन्वतरि कोविड केयर हास्पिटल स्थापित कर उसमें 170 डाक्टरों और अन्य पेशेवरों की तैनाती की है।

ब्रिटेन ने भेजे तीन आक्सीजन जेनरेटर, एक हजार वेंटिलेटर

ब्रिटेन ने दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान भरकर राहत सामग्री भेजी है। इसमें 18 टन आक्सीजन जेनरेटर और एक हजार वेंटिलेटर हैं। नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के अनुसार तीन यूनिट आक्सीजन जेनरेटर में से प्रत्येक से 500 लीटर प्रति मिनट लिक्विड आक्सीजन का उत्पादन हो सकेगा जो 50 मरीजों के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त होगी।

लॉकडाउन में मुंबई, दिल्ली और बिहार के लिए चलती रहेंगी ट्रेनें

लखनऊ। यात्रियों की कम मांग वाली ट्रेनों को रेलवे बोर्ड जहां बंद करने का निर्णय ले रहा है। वहीं लखनऊ से मुंबई, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और कोलकता के बीच चलने वाली ट्रेनें अभी चलती रहेंगी। क्योंकि इन राज्यों से लगातार श्रमिकों का पलायन जारी है। ऐसे में रेलवे बोर्ड लखनऊ से आवागमन करने वाली ट्रेनों को बंद करने की कोई मंशा नहीं जताई है। उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के परिचालन शाखा से जुड़े अधिकारी बताते है कि बोर्ड हर ट्रेनों पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। कम मांग वाली ट्रेनों की समीक्षा की जा रही है। रोजाना ट्रेनों में सीटों की बुकिंग और यात्री उपलब्ध की रिपोर्ट मांगी जा रही है। कोविड काल के दौरान जिन रेल खंडों पर यात्री कम हो रहे है उन रेल खंडों पर ट्रेनें आगामी दिनों तक बंद करने के संबंध में प्रस्ताव मांगे जा रहे है। जिसमें लखनऊ से चलने वाली ट्रेनों के नाम नहीं है।

चारबाग और लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेनें-लखनऊ मेल, गोमती एक्सप्रेस, पुष्पक सुपरफास्ट, मुंबई एसी सुपरफास्ट, लखनऊ आनन्द विहार, लखनऊ एसी एक्सप्रेस नई दिल्ली, लखनऊ बांद्रा, लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी, गोमतीनगर जयपुर के अलावा शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना, पाटिलपुत्र जैसे दर्जनों ट्रेनें है जो गैर राज्यों से श्रमिकों को लेकर लखनऊ पहुंच रही है। उन ट्रेनों को बंद करने का कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है। इन सभी ट्रेनों में 50 फीसदी सीटें खाली है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश-यूपी में तीन-चार माह में पूरा हो जाए वैक्सीनेशन

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोराना संक्रमण पर जल्दी काबू पाने के लिए राज्य सरकार से कहा कि सरकार टेंडर की लंबी प्रक्रिया अपनाने की बजाय सीधे इसकी खरीद का प्रयास करे क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है और तीसरी लहर आने की आशंका बनी है वायरस का म्यूटेशन इतना तेज होगा यह वैक्सीन के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देगा। ऐसे में अब तक किए गए सभी प्रयासों का वांछित परिणाम नहीं मिल सकेगा। कोर्ट ने सरकार को वैक्सीन शीघ्र हासिल करने का रास्ता खोजने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेशभर में टीकाकरण का कार्य तीन-चार माह में पूरा कर लिया जाए तभी इसका लाभ मिलेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि संक्रमण में भले ही कमी आ रही है लेकिन यह आराम से बैठने का समय नहीं है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा और मजबूत करने की जरूरत है।

कोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को जमाखोरों से जब्त किए गए रेमडेसिवर इंजेक्शन व अन्य जीवनरक्षक दवाएं जल्द रिलीज करने के लिए सम्बंधित मामलों का तीन दिन में निस्तारण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी से कहा कि सकुर्लर जारी कर सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश ?दें कि जब्त की गई दवाएं रिलीज कराने के लिए 24 घंटे में संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करें। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने मेरठ के ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में वहां के डीएम मेरठ की रिपोर्ट पर असंतोष जताया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीएम मेरठ ने कोर्ट को बताया कि मौतें किसी अन्य कारण से हुई हैं। हालांकि वह कोर्ट के इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि मौतें किस कारण से हुईं और उस दिन सेंटर में कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध थी। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट है कि डीएम ने सही तरीके से जांच नहीं की जबकि मामले पर न्यायिक स्तर से संज्ञान लेने के बाद उन्हें ऐसा करना चाहिए था। कोर्ट ने डीएम मेरठ को प्रकरण की विस्तृत जांच कर अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। लखनऊ के दो अस्पतालों में ऑक्सीजन होने के बावजूद मरीजों को लौटाने के मामले में डीएम लखनऊ ने हलफनामा पेश कर बताया कि सन हॉस्पिटल की जांच में आरोपों को सही पाया गया है। उन्होंने ऑक्सीजन होने के बावजूद मरीजों को लौटाया।

क्या है वैक्सीन पेटेंट, इसके हटने से कैसे पूरी दुनिया का होगा फायदा, भारत साथ पर अमीर देश क्यों हैं खिलाफ?

नई दिल्ली। अमेरिका ने कोरोना महामारी को देखते हुए पेटेंट हटाने को लेकर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही दुनिया में वैक्सीन की कमी से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इसके साथ ही यह भी तय है कि पेटेंट हटा तो दुनियाभर में टीके की कमी दूरी हो जाएगी। हालांकि अमीर देश पेटेंट हटाने के पक्ष में नहीं हैं। वहीं, भारत समेत दुनिया के कई देशों ने इसका समर्थन किया है।

क्या है वैक्सीन पेटेंट-आमतौर पर पेटेंट एक कानूनी अधिकार है। यह किसी भी तकनीक, खोज, सेवा या डिजाइन को बनाने वाली कंपनी, संस्था या व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे कि उसके उत्पाद का कोई नकल न कर सके। बिना अनुमति के अगर कोई कंपनी किसी उत्पाद को बनाने लगे तो वह गैरकानूनी होगा। इसके साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे होगा फायदा-विश्व में फिलहाल कोरोना के जितने भी टीके बन रहे हैं उन सभी कंपनियों के उस टीके का पेटेंट है। इसके साथ ही वैक्सीन का उत्पादन केवल वही कंपनी कर सकती है। ऐसे में अगर वैक्सीन पर से पेटेंट हटाया जाता है तो वैक्सीन को बनाने की तकनीक दूसरी कंपनियों को भी मिल जाएगी। इससे टीके की कमी दूर होगी और उसकी कीमत भी कम होगी।

सिर्फ कोरोना के लिए छूट-अमेरिकी

व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने कहा है कि जो बाइडन प्रशासन बौद्धिक संपदा की सुरक्षा का समर्थन करता है, लेकिन वैक्सीन पेटेंट में छूट सिर्फ कोरोना वायरस महामारी के खात्मे तक ही दी जाएगी। उन्होंने कहा, यह वैश्विक स्वास्थ्य संकट है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियां बड़ी पहल करने के लिए बाध्य कर रही हैं।

भारत समेत कई देश समर्थन में-भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल अक्तूबर में विश्व व्यापार संगठन से वैक्सीन पर से पेटेंट हटाने की मांग की थी। बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की इस मांग को फिलहाल 100 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया है। सबसे बड़ी बात अमेरिका ने भी इस पहल का समर्थन किया है। हालांकि बता दें कि पहले अमेरिका इसके विरोध में था।

अमीर देश पेटेंट के विरोध में-ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ समेत कई अमीर देश पेटेंट हटाना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा दुनियाभर की फार्मा कंपनियां भी इसके विरोध में हैं, क्योंकि फार्मा कंपनियों के लिए यह कमाई का बड़ा मौका है। इसके साथ ही इन कंपनियों का कहना है कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर इन वैक्सीन को बनाया है। विशेषज्ञों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सदस्य देशों को कोविड-19 टीकों को लेकर पेटेंट नियमों में छूट के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिये तत्काल बातचीत शुरू करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है, उसके लिए यह जरूरी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के डब्ल्यूटीओ में कोविड-टीकों को लेकर पेटेंट नियमों में छूट देने के प्रस्ताव को अमेरिका के समर्थन के साथ विशेषज्ञों ने यह बात कही। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में कोविड-19 संक्रमण के इलाज, उसकी रोकथाम के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों के लिए ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट देने का प्रस्ताव किया।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

टीके का इंतजाम

यह अब स्पष्ट हो गया है कि कोविड नियंत्रण में व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम का महत्व सबसे ज्यादा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं, अगर किसी देश में लगभग सत्तर प्रतिशत जनसंख्या को टीका लग जाए, तो यह लगभग तय है कि उस देश से कोविड का उन्मूलन हो जाएगा। कई देश इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ देश जल्दी ही पूरी जनसंख्या को टीका लगाने का लक्ष्य पा लेंगे। ग्रेट ब्रिटेन ने तो लोगों को तीसरी खुराक देने की योजना बनाना भी शुरू कर दिया है। कई साधनहीन देश जरूर इस दौड़ में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि साधन संपन्न देशों ने पहले अपने नागरिकों को टीके मुहैया कराने को प्राथमिकता दी है। भारत में हालांकि खुद दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली संस्थाएं हैं, लेकिन इस दौड़ में यह काफी पिछड़ गया है। इसकी वजह यह रही कि हमारी सरकार ने वैक्सीन की जरूरत के मुताबिक योजना बनाकर पहले ऑर्डर नहीं दिए। अब जब भारत में कोरोना की ताजा लहर भयावह रूप ले चुकी है, तब तेजी से टीके लगाने की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। सरकार ने यह एक अच्छा काम किया है कि दुनिया के कई टीकों को भारत में लगाने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सरकार ने कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनजर इस दौरान वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार के दायरे से बाहर रखने की बात कही है। इन वजहों से भारत में टीकाकरण की रफ्तार तेज होगी, लेकिन इन सबका असर जमीन पर दिखने में अभी कुछ वक्त लगेगा। टीकों की भारत में उपलब्धता आसान करने के लिए सरकार एक और कदम उठा सकती है कि टीका निर्माताओं को टीकों के संभावित दुष्प्रभावों के लिए कानूनी बाध्यता से मुक्त कर दे। टीका निर्माताओं की हिचकिचाहट का एक बड़ा कारण इससे खत्म हो जाएगा। अगर किसी पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसके लिए सरकार अपने स्तर पर नुकसान भरपाई और मुआवजे का इंतजाम कर सकती है। इसके लिए सरकार चाहे, तो किसी बीमा कंपनी से करार कर सकती है। इस मामले में खतरे या फिक्र की बात इसलिए भी नहीं है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को टीके लग चुके हैं और ऐसी कोई खबर नहीं आई है, जिससे किसी गंभीर खतरे का आभास हो। जाहिर है, कोई भी दवा या वैक्सीन शत-प्रतिशत निरापद नहीं होती, लेकिन अभी जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, उनसे दुष्प्रभावों की संख्या नगण्य है। इसलिए वैक्सीन की सुरक्षा की गारंटी सरकार ले, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा ।

भारत जैसे देश में इस बात का ज्यादा महत्व इसलिए है कि यहां सरकार की विशेष विश्वसनीयता होती है। अगर लोग यह जानेंगे कि सरकार सुरक्षा की गारंटी ले रही है और किसी आकस्मिक मुश्किल के वक्त वह हमारी मदद करेगी, तो वैक्सीन के प्रति अगर कुछ हिचक है भी, तो वह कम होगी। वैसे भी आम भारतीयों के लिए किसी कंपनी के बजाय अपनी सरकार से शिकायत करना ज्यादा आसान होगा। इस तरह, यह स्थिति वैक्सीन निर्माताओं के लिए भी ठीक होगी और हमारे नागरिकों के लिए भी। यह देखा जा रहा है कि कोविड राहत से जुड़े कई मामलों में बहुत छोटे-छोटे तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दों की वजह से देर हो रही है, जो कि ऐसी आपात स्थिति में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सरकार को टीकों की उपलब्धता तेजी से बढ़ाने के लिए जो भी करना जरूरी हो, तुरंत करना चाहिए।

जीवन का अर्थशास्त्र

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना जो नया आकलन पेश किया है, वह चिंता बढ़ाने वाला है। आकलन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2021-22 में 9.5 प्रतिशत ही रह सकती है। गौरतलब है कि इसी संस्था ने जनवरी, 2021 में अपने आकलन में कहा था कि वित्त वर्ष (2021-22) में भारतीय अर्थव्यवस्था 11 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज करेगी यानी इस संस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति अपनी उम्मीदों को थोड़ा और कम किया है। ऐसा स्वाभाविक है। कोरोना कहर ढा रहा है, खासकर उन इलाकों में भी, जिनका महत्वपूर्ण योगदान आतथक विकास में होता है, जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। कोरोना की दूसरी लहर को थामने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर तेज बहस के बीच आतथक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे किसी भी कदम से इकोनॉमी को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी। उद्योग संगठन पीएचडी चेंबर के प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन की सूरत में पिछले वित्त वर्ष की तरह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी 23 फीसद से अधिक की गिरावट हो सकती है। पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में कामगार सड़क पर आ जाएंगे। स्टेट बैंक आफ इंडिया के मुख्य आतथक सलाहकार एसके घोष के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण और अलग-अलग होने वाले लॉकडाउन से अब तक दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। फिर भी, अच्छी बात यह है लॉकडाउन और प्रतिबंध स्थानीय स्तर पर ही सिमटे हैं जिससे रोजगार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उद्योग संगठन सीआईआई के प्रमुख उदय कोटक ने भले ही राष्ट्रीय लॉकडाउन की वकालत की हो, लेकिन संगठन की मुख्य अर्थशास्त्री बिदिशा गांगुली का मानना है कि इस बार स्थिति अलग है। राज्य अपने-अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा रहे हैं और यही उचित है। देशव्यापी लॉकडाउन से सप्लाई चेन प्रभावित होती है जिससे निर्यात प्रभावित होगा। अभी वैश्विक मांग अच्छी होने से निर्यात में बढ़ोतरी का रुख जारी है यानी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाना है, तो जीवन के साथ साथ आजीविका की चिंता भी करनी पड़ेगी और समग्र राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जैसे किसी भी कदम को बहुत ही सोच-समझ कर उठाया जाना चाहिए।

कटाक्ष/कबीरदास

'चलता है' पर कब तक?

भाई विरोधियों की ये बात ठीक नहीं है। कोविड का विरोध छोड़कर, प्रधानमंत्री के नये बंगले का ही विरोध करने लगे। एक सौ पैंतीस करोड़ भरतीयों का प्रधानमंत्री क्या अपने लिए एक न्यारा बंगला भी नहीं बनवा सकता! जो देश स्वतंत्रता के बाद से 'इक बंगला बने न्यारा' गा-सुनकर बड़ा हुआ है, जिस देश का एक-एक नागरिक आज भी एक न्यारा बंगला बनाने का सपना देखता है, वह देश क्या प्रधानमंत्री के लिए एक नया बंगला बनवाने में भी कंजूसी करेगा? फिर मोदी जी का महल बनवाने का शोर क्यों? अब एक सौ पैंतीस करोड़ के चुने हुए प्रधानमंत्री का बंगला, छोटे-मोटे राजमहल से कम क्या होगा!

जो लोग महामारी के बीच में बंगला बनने का शोर मचा रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही नासमझ हैं। वे क्या जानें संकट के बीच महल-मकबरे बनाने की, हमारे सुल्तानों-महाराजाओं की पुरानी परंपरा का महात्म्य? बाढ़ हो, सूखा हो, अकाल हो, जब-जब प्रजा पर भारी संकट आता था, तब-तब शाह-ए वक्त कुछ न कुछ बड़ा बनवाता था। कोई-कोई तो दिन भर बनवा कर, रात को तुड़वाता था और फिर अगले दिन बनवाता था। न सही शाह का नाम, पर पब्लिक के लिए तो हो काम! इसीलिए, कोरोना संकट आता देखकर ही मोदी जी ने राजधानी का नया दिल बनाने के अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में पूरा जोर लगा दिया। और दूसरी लहर के जोर पकड़ते ही खुदाई भी शुरू हो गई है। तीसरी लहर आते न आते, राजधानी का नया दिल बनकर तैयार हो जाएगा। पता नहीं क्यों लोग ये दिल पत्थर का होने के पीछे पड़े हैं! स्मारक तो तभी टिकाऊ होता है और लोगों को काम के साथ, शाह को नाम देता है जब पत्थर से बने। इसकी जगह मोदी जी अगर हजार-पांच सौ अस्पताल बनवा भी देते, आक्सीजन के सौ-दो सौ कारखाने लगवा भी देते, तो भी उससे क्या हो जाता? पच्चीस-पचास हजार जानें बच जातीं बस। पर तरक्की के नाम पर देश को क्या मिलता-ठेंगा? नया सेंट्रल विस्टा छोड़ो, प्रधानमंत्री के लिए न्यारा बंगला तक नहीं मिलता। चंद जानें एक तरफ पीएम का बंगला एक तरफ-आप होते तो क्या चुनते? मत भूलो कि हम एक सौ पैंतीस करोड़ हैं!

इबोला से सबक सीखे भारत

निखिल पांधी

पश्चिमी अफ्रीका में इबोला महामारी ने 28,616 लोगों को संक्रमित किया था और 2014 से 2016 के बीच सिएरा लियोन, लाइबेरिया और गिनी में 11,310 लोगों की मौत हुई थी। इबोला से हुई वह त्रासदी भले ही एक क्षेत्र विशेष की थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के समय वह गौरतलब है। आज जब दूसरी लहर भारत को कुचल रही है, तब सूक्ष्म और स्थूल, दोनों स्तरों पर इबोला संकट से हम सबक ले सकते हैं। सबसे पहले, इबोला की तरह ही कोविड-19 को भी देखभालकर्ता को भी होने वाली बीमारी के रूप में माना जाना चाहिए। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला के इलाज से जमीनी स्तर पर जुड़े रहे विश्व प्रसिद्ध संक्रामक रोग चिकित्सक और मानव विज्ञानी पॉल फार्मर ने अपनी पुस्तक फेवर्स, फ्यूड्स ऐंड डायमंड्स : इबोला ऐंड द रैवेजेज ऑफ हिस्ट्री में लिखा है - महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों लोगों को इबोला इसलिए हुआ, क्योंकि वे बीमार लोगों की सेवा व मृतकों के अंतिम संस्कार में लगे थे। कोविड-19 के मामले में भी पहचानना जरूरी है कि यह देखभाल करने वालों, जैसे डॉक्टरों, नर्सों व पैरा-मेडिकल स्टाफ से लेकर घर, अस्पताल, क्लिनिक और श्मशान में काम करने वालों को प्रभावित कर रहा है। आज सेवा में लगे लोगों को अपने छोटे-छोटे प्रयास के स्तर पर कमियों को पहचानने व सुधार करने की जरूरत है।

टीकाकरण से परे भारत सरकार को कोरोना के खिलाफ मोर्चा ले रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को जोखिम से बचाने के लिए ठोस योजना विकसित करनी चाहिए। अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं की कमी का जोखिम बहुत वास्तविक है। श्मशान, कब्रिस्तान और मोर्चरी में कार्यरत लोग आम तौर पर दलित-दमित वर्ग से आते हैं, क्या उन्हें राज्य मान्यता देता है? क्या ऐसे उपेक्षित श्रमिकों (और उनके परिवारों) के लिए सरकार ने किसी बीमा की व्यवस्था की है? साफ है, इबोला या कोरोना से पीड़ित लोगों के साथ-साथ उनकी तिमारदारी करने वालों को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाए। दूसरा, संक्रमितों की देखभाल-क्षमता का विकास पहले करने के बाद ही कंटेनमेंट बनाकर वायरस से मुकाबले के निर्देश जारी किए जाने चाहिए। लॉकडाउन की घोषणा और सिर्फ जबरदस्ती से रोकथाम के उपाय लागू करना अपने आप में कोई समाधान नहीं है। इबोला के मामले में पॉल फार्मर चर्चा करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बायो-मेडिसिन राज्य के सामाजिक अनुबंध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सुरक्षित और प्रभावी देखभाल सुनिश्चित किए बिना रोकथाम की नीति की अपनी सीमाएं हैं। इबोला के समय भली-भांति देखा गया था कि ऐसा करना न सिर्फ पीड़ितों के जीवन को खतरे में डालता है, बल्कि राज्य के खिलाफ आक्रोश भी पैदा करता है, जो अविश्वास का रूप ले सकता है। अपने हाल पर छोड़ दिए गए लोग कंटेनमेंट, संपर्क-ट्रेसिंग और टीकाकरण का विरोध भी कर सकते हैं।

> वैज्ञानिकों और वायरोलॉजिस्टों के साथ, जिनके प्रयास महत्वपूर्ण हैं, भारत सरकार को अपनी आपदा तैयारियों में समाज विज्ञानियों, सामुदायिक स्वयंसेवकों और नियमित रूप से समाज पर नजर रखने वाले लोगों को शामिल करना चाहिए।

तीसरा, भारत में मौजूदा संकट इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि अस्पताल जरूरत से ज्यादा दबाव में आ गए हैं, और राज्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम है, ऑक्सीजन, बिस्तर, उपकरण, दवाएं और टीके का अभाव है। इबोला संकट भी यही दर्शाता है कि बुनियादी कर्मचारियों, सामग्री और देखभाल की व्यवस्था का अभाव था। पश्चिमी अफ्रीका में स्वतंत्र इबोला उपचार इकाइयां सामुदायिक सक्रियता के माध्यम से स्थापित की गई थीं और दूसरे व तीसरे स्तर की चिकित्सा की अनुपस्थिति में दो साल तक कायम थीं। भारत में उन इलाकों में चिकित्सा इकाइयों को तेजी से विकसित करना चाहिए, जिनके आसपास लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, जहां अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। लोग कोरोना से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जान गंवा रहे हैं। अभी बुनियादी चिकित्सा ढांचे की अनुपस्थिति भारी पड़ रही है। आज जांच और इलाज के लिए तत्काल चिकित्सा इकाइयों और ऑक्सीजन हब बनाने की जरूरत है। चौथा, हम वायरल महामारी में स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों की उपेक्षा नहीं कर सकते। भारत में चल रही दूसरी लहर में संक्रमण और चिकित्सा व्यवस्थाओं की विफलता मध्य व उच्च-मध्य वर्गों को प्रभावित कर रही है। यह 2020 की पहली लहर से अलग है, जिसमें सबसे पहले दुर्बल श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गरीब व सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित ज्यादा निशाने पर थे। हमें खुद से पूछना चाहिए, राज्य, मीडिया, नागरिक (नेटिजन सहित) और चिकित्सा व्यवस्थाएं पहली और दूसरी लहर के बीच के समय में पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम क्यों रहीं? वर्तमान दौर दर्शाता है कि वर्ग और जाति के आधार पर संकट व देखभाल की हमारी धारणा कैसे तय की जाती है? हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति तभी गंभीर होते हैं, जब उच्च वर्ग के लोग शिकार होने लगे।

पांचवां, वायरस हमेशा समाज में कमजोरियों का पीछा करते हैं, और समाज की दरारों व कमियों पर हमला बोलते हैं। जैसा कि पॉल फार्मर ने एक साक्षात्कार में कहा था, महामारी की शुरुआत में एक भ्रम होता है कि यह नया वायरस समाज में सभी वर्गों, लोगों को समान रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आज वायरस की गति को समझने और उसे काबू करने के लिए हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील ढंग से समझना चाहिए। इबोला के मामले में पॉल फार्मर इतिहास में समस्या की जड़ें तलाशते हैं। उपनिवेशवाद व उत्तर-औपनिवेशिक गृह युद्धों, जातीय संघर्ष और शोषणकारी संरचनात्मक ढांचा इबोला से मची तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय संदर्भ में देखें, तो स्वास्थ्य के प्रति सरकारों के रवैये का आधार नस्ल, वर्ग, लिंग या जातीयता नहीं रही है। इसी वजह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सामाजिक या सरकारी प्राथमिकता के रूप में आकार लेने से रोका। ऐसे में, बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी पीड़ितों पर ही डाल देना आम बात है। वैज्ञानिकों और वायरोलॉजिस्टों के साथ, जिनके प्रयास महत्वपूर्ण हैं, भारत सरकार को अपनी आपदा तैयारियों में समाज विज्ञानियों, सामुदायिक स्वयंसेवकों और नियमित रूप से समाज पर नजर रखने वाले लोगों को शामिल करना चाहिए। सिर्फ इबोला ही नहीं, एड्स जैसी वैश्विक महामारियों के रिकॉर्ड से भी इलाज की खास जरूरतों की पूर्ति, कमजोर समूहों की पहचान और मौजूदा देखभाल उपायों का सही पता चलता है। इबोला से सीखते हुए हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था ही वायरस जनित खतरों को जवाब दे सकती है। कोई आपातकालीन व्यवस्था नहीं, बल्कि ऐसी रोजमर्रा की व्यवस्था ही आपदा से मुकाबले के लिए खड़ी होती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पश्चिम बंगाल

क्षेत्रीय अस्मिता और पंथ निरपेक्षता का प्रश्न

विश्वनाथ सचदेव

चुनाव तो देश के पांच राज्यों में हुआ था, पर देश भर की निगाहें पश्चिम बंगाल पर थीं। परिणाम सामने है, भाजपा दक्षिण में पैर रखने की जगह तलाश रही थी। पुडुचेरी में उसे पैर का अंगूठा टिकाने की जगह मिल गयी है। तमिलनाडु और केरल दोनों जगह भाजपा की सारी कोशिशें नाकामयाब रही हैं। असम में वह अपनी स्थिति मज़बूत बनाये रखने में सफल हो गयी है। लेकिन, पश्चिम बंगाल में, जहां लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भीषण थी, भारतीय जनता पार्टी की सारी कोशिशें विफल रही हैं। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और भाजपा के बाकी सारे दिग्गज बंगाल में दो सौ से अधिक सीटें अपनी झोली में होने के दावे कर रहे थे, पर वे सारे दावे खोखले सिद्ध हुए। दो सौ से अधिक सीटें 'दीदीईईई' की पार्टी को मिलीं। पर क्या यह सारा 'खेला' दो पार्टियों की हार-जीत का ही था?

उत्तर है, नहीं।

पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में देश पर एकछत्र राज का सपना देखने वाली भाजपा ने अपनी सारी ताकत झोंकी थी। देश के इतिहास में यह शायद पहली बार है कि एक राज्य के चुनाव के लिए देश के प्रधानमंत्री ने इतनी ज़्यादा नाकामयाब कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के इस चुनाव में बीस से अधिक रैलियां की थीं, और देश के गृहमंत्री ने पचास से अधिक। यह रैलियां उस अवधि में हुई जब देश कोरोना की दूसरी लहर यानी सुनामी को झेल रहा था। सवाल पूछा गया था, और अब भी पूछा जा रहा है कि सरकार, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को इस चुनाव को स्थगित करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? क्या आसमान टूट पड़ता यदि ये चुनाव दो-चार महीने बाद होते? भीड़ भरी रैलियों में अपनी लोकप्रियता और सफलता देखने वाले हमारे राजनेताओं को कहीं नहीं लगा कि यह भीड़ कोरोना को निमंत्रण देने वाली है! यह विडम्बना ही है कि सारे चुनाव अभियान में एक बार भी कोरोना का नाम न लेने वाली ममता दीदी की नयी सरकार को सबसे पहले अपने राज्य में कोरोना से जूझना पड़ रहा है।

बहरहाल, बंगाल के इस चुनाव में दांव पर हमारे संवैधानिक मूल्य भी थे। हमारा देश पंथ-निरपेक्ष है। हमारा संविधान हर धर्म को पनपने का अवसर देने का वादा करता है। हमारी परम्परा यह कहती है कि राजनीतिक वर्चस्व के लिए किसी को भी धर्म का सहारा लेने की आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। इसके बावजूद हमने देखा कि धर्म के नाम पर खुलेआम वोट मांगे गये। लेकिन जिस तरह, इस बार 'जयश्रीराम' को एक चुनावी नारा बना दिया गया, वह संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना नहीं, संविधान के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी टक्कर में चुनावी मंचों में ममता बनर्जी का 'चण्डी पाठ' भी वोट-जुटाऊ कोशिश ही कहा जायेगा। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में हमारे बड़े नेताओं ने इस दुरुपयोग के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं।

इस संदर्भ में चुनाव आयोग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ममता बनर्जी की पार्टी ने तो शुरू में ही आरोप लगाया था कि आठ चरणों में चुनाव कराने का निर्णय भाजपा के संकेत पर लिया गया है। आयोग की कार्रवाई के पीछे तर्क दिये जा सकते हैं, पर संदेह का आधार भी कमज़ोर नहीं है। चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना ही नहीं, निष्पक्ष दिखना भी ज़रूरी है, और इस कसौटी पर, दुर्भाग्य से, हमारी यह संवैधानिक संस्था सफल होती नहीं दिख रही। चुनाव-आयोग यदि चाहता तो रैलियों में भगवान राम की जय के नारे लगाने पर रोक लगा सकता था। हमारे राजनेताओं ने चुनावों के लिए इनका उपयोग करके इसकी महत्ता को कम करने की ही कोशिश की है। हमें सोचना होगा कि भविष्य में धार्मिक भावनाओं को उभारने की राजनीति पर किस तरह रोक लगायी जाये।

धर्म के नाम पर मतदाताओं को बांटने और ध्रुवीकरण करने की यह राजनीति हमारे संवैधानिक मूल्यों और सह अस्तित्व की हमारी परम्पराओं से मेल नहीं खाती। हमारा बहुधर्मी समाज होना और पंथ-निरपेक्षता हमारी ताकत है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले हमारी इस ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं। हमारी संवैधानिक मर्यादाओं का भी तकाज़ा है कि हम राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का सहारा लेने वालों को प्रश्रय न दें।

एक बात और जो हमारे राजनेताओं को याद रखनी चाहिए, वह यह है कि भाषा की शालीनता और मर्यादा सार्वजनिक जीवन में शुचिता की महत्वपूर्ण शर्त है। भाजपा भले ही स्वीकारे या न स्वीकारे, पर देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने इस चुनावी लड़ाई में 'दीदी' शब्द की महत्ता को नहीं समझा। बंगाल की महिलाओं ने इसे अपनी संस्कृति की उपेक्षा, या कहना चाहिए संस्कृति के अपमान, के रूप में लिया। कम से कम अब तो हमारे नेताओं को यह समझ आ ही जाना चाहिए कि क्षेत्र-विशेष की संस्कृति की दुहाई देने और उसका आदर करने में अंतर होता है। बंगाल के मतदाता ने हमारे राजनेताओं को यह अंतर समझाने की कोशिश की है। पर यह तय है कि इस चुनाव में, और चार अन्य राज्यों के चुनाव में भी, मतदाता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी उपेक्षा या उसे कमतर आंकना, उसे स्वीकार नहीं है।

परीक्षा

रद्द करना सही उपाय नहीं

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी

कोरोना महामारी ने जीवन के हरेक क्षेत्र को प्रभावित किया है जिसमें शिक्षा भी एक महद्भवपूर्ण क्षेत्र है। शिक्षा क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा असमंजस बोर्ड की परीक्षाओं के लेकर था। कोरोना के कारण बिगडते हालात को देखते हुए सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया है। सीबीएसई की गाइड़लाइंस के अनुसार आंतरिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर 10वीं कक्षा के सभी बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसमें सबसे महद्भवपूर्ण बिंदु यह है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले ज्यादातर छात्र आंतरिक परीक्षाओं को गंभीरता से नहीं लेते। प्राप्तांकों के कम होने पर भी उनका फोकस केवल बोर्ड परीक्षा पर ही रहता है। ऐसी स्थिति में मेधावी और औसत छात्रों के बीच प्राप्तांकों में कम अंतर रह जाने के कारण सभी छात्र लगभग एक स्तर पर ही दिखाई देंगे। इसलिए मूल्यांकन करने का यह तरीका मेधावी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ न्याय नहीं करता।

दसवीं कक्षा की परीक्षा रद्द होने से स्कूल उन बच्चों की आंतरिक परीक्षाएं करवा रहे हैं, जिन्होंने आंतरिक परीक्षाएं दी ही नहीं थीं। इसका सीधा प्रभाव उन विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, जिन्होंने आंतरिक परीक्षा को गंभीरता से न दिए जाने के कारण बहुत कम अंक प्राप्त किए हैं। क्या ऐसे छात्रों को दुबारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? इसका एक दूसरा पहलू भी है कि प्रत्येक स्कूल अपने परीक्षा परिणाम को अच्छे से अच्छा दिखाने का प्रयास करेगा इसके लिए भी सीबीएसई ने गाइड़लाइंस दी हैं कि प्रत्येक स्कूल अपने परीक्षा परिणाम में पिछले तीन वर्षों के आधार पर 2 प्रतिशत तक की ही वृद्धि कर सकता है। अब प्रत्येक स्कूल प्रशासन ही यह तय करेगा कि वह अपने कितने बच्चों को किस रैंक में उत्तीर्ण करना चाहता है जिसका सीधा असर बच्चों की आगे की पढ़ाई पर भी पड़ेगा। सीबीएसई के साथ-साथ लगभग सभी राज्यों के बोड़ों और आईसीएसई के 10वीं के बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में ओपन बोर्ड में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करना कितना न्यायसंगत होगा। यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है।

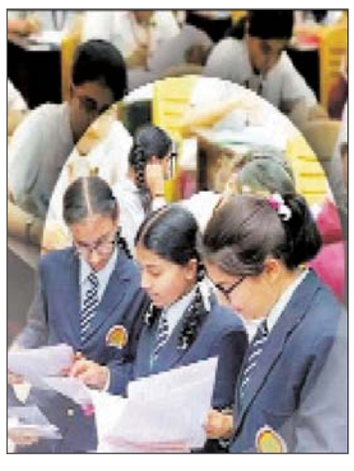

पिछले वर्ष भी लॉकड़ाउन के कारण 10वीं एवं 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। बच्चों द्वारा दी गइफ परीक्षाओं के औसत के आधार पर बाकी अन्य विषयों में भी औसत अंक दे दिए गए थे परंतु पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की स्थितियां काफी अलग हैं। आने वाले समय में ऑनलाइन कक्षाओं के महद्भव को देखते हुए प्रत्येक स्कूल द्वारा इसके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। सीबीएसई के सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं वर्ष भर सुचारू रूप से चली हैं। ऐसे में प्रत्येक राज्य से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन कक्षाओं की कितनी तैयारी की है। पिछले एक वर्ष से ऑनलाइन शिक्षा के लिए ब्रॉड़बैंड सेवा की उपलब्धता और कनेक्टिविटी की स्थिति को सुधारने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं और वर्ष भर में कितनी कक्षाएं ऑनलाइन ली गई हैं। इन सब प्रश्नों से बचने का सबसे आसान तरीका है परीक्षाओं को रद्द कर देना।

परीक्षा करवाना महद्भवपूर्ण नहीं होता, बल्कि परीक्षा के लिए बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना सबसे महद्भवपूर्ण होता है। 10वीं की परीक्षाएं बच्चों के लिए सिर्फ सफलता का पैमाना ही नहीं होतीं, बल्कि व्यक्तित्व के निर्माण की नींव भी रखती हैं। परीक्षाओं के कारण ही विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन आता है, सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना का भी विकास होता है। ऐसी स्थिति में जब स्कूलों को ही रिजल्ट देने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो इसके साथ यह व्यवस्था भी की जा सकती थी कि प्रत्येक स्कूल अपने स्तर पर ऑनलाइन परीक्षाएं संपन्न करवाए।

दूसरी व्यवस्था यह हो सकती थी कि सिलेबस को कम करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के आधार पर भी स्कूलों को ही ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती। ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि पेपर लीक जैसी समस्या भी नहीं रहती जिससे न सिर्फ बच्चों में परीक्षा के प्रति जागरूकता बनी रहती है, बल्कि सब बच्चों के साथ न्याय भी होता है। 10वीं के बच्चों के संवेदनशील मन को जीवन के सपनों को बुनने के लिए अवसर देना भी हमारी ही जिममेदारी है।

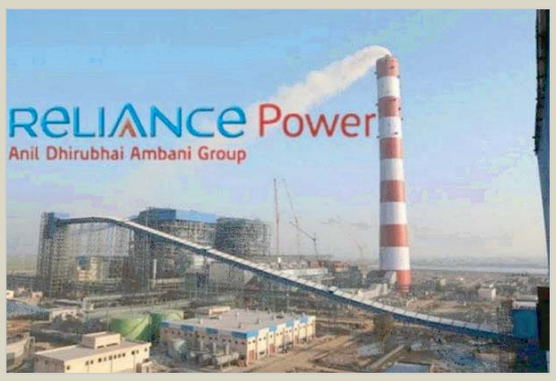

रिलायंस पावर को मार्च की तिमाही में 72.56 करोड़ रुपए का मुनाफा

नई दिल्ली: रिलायंस पावर ने मार्च 2021 को समाप्त तिमाही में 72.56 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध मुनाफा कमाया। कंपनी ने मार्च 2020 में समाप्त तिमाही में 4,206.38 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध घाटा अर्जित किया था। कंपनी की कुल आय इस सान मार्च तिमाही में 1,691.19 करोड़ रुपए थी। एक साल पहले इसी अवधि में इसने 1,902.03 करोड़ रुपए की आय दिखाई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में, कंपनी का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 228.63 करोड़ रुपए था, जबकि 2019-20 में यह 4,076.59 करोड़ रुपए था। वर्ष 2020-21 में कंपनी की कुल आय 8,388.60 करोड़ रुपए थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 8,202.41 करोड़ रुपए थी।

मुकेश अंबानी को टक्कर देने के लिए Amazon का बड़ा दांव, किया 915 करोड़ रुपए का निवेश

बिजनेस डेस्क: अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अमेजन सेलर सर्विसेज में 915 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है। नियामक दस्तावेज के अनुसार यह ताजा निवेश भारत में अमेजन को अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों का आक्रामक रूप से सामना करने में मदद मिलेगी। फ्लिपकार्ट की वालमार्ट और मुकेश अंबानी की जियोमार्ट उसके दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। कारोबार जगत पर अनुसंधान करने वाले समूह टॉफलर ने कंपनी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में जमा रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि अमेजन कॉर्पोरेट होल्डिंग्स और अमेजनडॉटकॉमडॉटआईएनसी ने अमेजन सेलर सर्विस में 915 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दस्तावेजों से पता चला है कि अमेजन कॉर्पोरेट होल्डिंग्स को 91,49,57,723 शेयर तथा अमेजनडॉटकॉमआईएनसी को समझौते में 42,277 शेयर दिए गए हैं। अमेजन इंडिया ने इस संबंध में ईमेल के जरिए भेजे गए का सवाल पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्लेखनीय है कि भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अमेजन बाज़ार मंच, थोक और भुगतान व्यवसाय क्षेत्र में कई अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। पिछले वर्ष जनवरी में अमेजन के सस्थापक जेफ़ बेज़ोस ने भारत में छोटे और मध्यम व्यवसायों को ऑनलाइन लाने में मदद करने के लिए सात हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की थी। इससे पहले भी अमेजन ने देश में 5.5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की थी। अमेरिका के अलावा भारत अमेजन के सबसे अहम बाजारों में से एक हैं।

भारत ने ऑक्सीजन के लिए ओपेक देशों का रुख किया

नयी दिल्ली. कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सीय ऑक्सीजन जुटाने के लिए भारत ने ओपेक देशों खासकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कुवैत का रुख किया है। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए देश में चिकित्सीय ऑक्सीजन की भारी कमी को पूरा करने के लिए भारत के पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ताओं की तरफ रुख किया और सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन के अपने समकक्षों के साथ विचार-विमर्श किया। प्रधान ने ट्विटर पर लिखा, ÷पिछले हफ्ते मैंने सऊदी अरब, यूएई और कतर के अपने समकक्षों के साथ भारत में एलएमओ (तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन) का आयात बढ़ाने के तरीकों पर करीबी विचार-विमर्श किया। मैं खासकर यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब की ओर से मुफ्त एलएमओ की प्रर्भिक आपूर्ति के साथ साथ सदभावना दिखाने की सराहना करता हूं।

हॉलमार्किंग के नियम को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की ज्वैलर्स को बड़ी राहत, अब नहीं लगेगा जुर्माना

बिजनेस डेस्क:

गोल्ड ज्वैलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्वैलर्स को बड़ी राहत दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के मामले में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते हॉलमार्किंग प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पा रहे ज्वैलर्स पर कड़ा एक्शन लेने या जुर्माना लगाने से **BIS** को रोक दिया है। यह रोक अगली सुनवाई 14 जून 2021 तक होगी। नागपुर बेंच ने इस बारे में 7 मई को एक अंतरिम आदेश पारित किया। उल्लेखनीय है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (**BIS**) के प्रावधानों के तहत देश में गोल्ड ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग 1 जून 2021 से अनिवार्य होने वाली है। इस नए नियम के लागू होने के बाद ज्वैलर्स बिना हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वैलरी न ही स्टोर कर सकेंगे और न ही बेच सकेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तर्क यह है कि गोल्ड ज्वैलरी पर 1 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के प्रावधान से देश के 5 लाख ज्वैलर्स के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कोर्ट में इस मामले में रिट पिटीशन ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डॉमेस्टिक काउंसिल (**GJC**) ने दायर की थी। **GJC**, ज्वैलर्स के प्रमोशन, प्रोटेक्शन और उन्नति को सुनिश्चित करती है। **GJC** के चेयरमैन आशीष पीठे के अनुसार, अदालत ने ज्वैलर्स की मुश्किलों को देखा। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अगली मुश्किल यह है कि ज्वैलर्स की संख्या के अनुपात में देश में हॉलमार्किंग सेंटर्स का प्रतिशत, 733 जिलों का लगभग 34% है। भारत में ऐसे 488 जिले हैं, जहां कोई हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है। अभी ज्वैलरी के लगभग 6000 करोड़ पीस ऐसे हैं, जिनकी हॉलमार्किंग होना बाकी है। अक्षय तृतीया 14 मई को है जबकि पिछले वर्ष अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को थी और देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन होने से ज्वैलर्स की बिक्री नहीं हुई थी। इस बार भी कई राज्यों ने लॉकडाउन लगा रखा है ऐसे में इस बार भी बिक्री पर असर पड़ना तय है।

गेहूं की सरकारी खरीद 50% बढ़कर पहुंची 323.67 लाख टन पर

नई दिल्ली: गेहूं की खरीद चालू रबी विपणन सत्र 2021-22 में अब तक 50 प्रतिशत बढ़कर 323.67 लाख टन हो गई है। इसमें 32 लाख से अधिक किसानों को जिसमें 63,924.56 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद का कार्य करती हैं। एमएसपी भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि छह मई तक कुल गेहूं खरीद 323.67 लाख टन रही। पिछले साल इसी अवधि में 216 लाख टन खरीद हुई थी। मंत्रालय ने कहा, एमएसपी पर 63,924.56 करोड़ रुपए की खरीद से अब तक लगभग 32.21 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। गेहूं की खरीद- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और बिहार में जारी है।

स्टार्टअप कंपनियों के लिए शेयर-सूचीबद्धता नियमों में ढील अधिसूचित

नई दिल्ली:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टार्टअप्स कंपनियों को बाजार में शेयर सूचीबद्ध करने को प्रोत्साहित करने के किए नियमों में कुछ ढील दी है। इसमें शेयर निर्गम से पहले की पूंजी को पास में बनाए रखने की अवधि कम किए जाने तथा कंपनी को इस बाजार मंच के पात्र निवेशकों को स्व-विवेक से 60 प्रतिशत तक शेयर आवंटन करने की छूट शामिल है। नए नियम पांच मई से लागू हो गए है। सेबी की तरफ से बुधवार को जारी दो अलग-अलग सूचनाओं में बताया गया कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर शेयर सूचीबद्ध कराने के लिए नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है की सेबी ने मार्च में स्टार्टअप की लिस्टिंग के नियमों में दी ढील देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही बाजार से शेयर हटाने की शर्त में भी ढील दी गयी है ताकि स्टार्टअप के लिए इस मंच पर आना और निकलना आसान हो। वहीं विनियामक ने मान्यता प्राप्त निवेशक द्वारा निर्गम पूर्व पूंजी का 25 फीसदी एक साल तक अपने पास बनाए रखने की शर्त रखी है। पहले यह अवधि दो साल थी। साथ ही मान्यता प्राप्त निवेशक की परिभाषा को इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म निवेशक कर दिया गया है। सेबी ने फैसला किया है कि इनोवेटर ग्रोथ इन्वेस्टरों पर निर्गम लोन वाली कंपनी को निर्गम के 60 फीसदी तक शेयर अपने विवेक से आवंटित करने की छूट होगी। ऐसे शेयर सूचीबद्धता के 30 दिन बाद ही बेचे जा सकेंगे।

Covid-19ः भारत की मदद के लिए अमेरिकी कंपनियों ने बढ़ाया हाथ, भेज रहीं सहायता सामग्री

वाशिंगटन:

अमेरिकी कंपनी जगत भारत को कोविड-19 महामारी के प्रकोप का सामाना करने में मदद के लिए सहायता सामग्री बढ़ाने में लगा है। कंपनियां यहां से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसेंटेटर आदि भेजने में जुटी हैं ताकि वहां तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों की प्राण रक्षा में मदद हो सके। भारत में इस समय हर दिन 4 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जा रहे है। अस्पताल खाट और ऑक्सीजन सहायता की कमी से जूझ रहे हैं। थर्मो फिशर ने शनिवार को यूनाइटेड एयरलाइन की मदद से भारत के लिए आवश्यक सहायता सामग्री की एक खेप रवाना की। कंपनी ने कहा, ÷हम विनम्रता के साथ कोविड-19 का सामाना करने के भारत के अपने साथियों वहां के लोगों की यह सहायता करना चाहते हैं।÷ कंपनी की ओर से भेजी गई सामग्री में 46 लाख वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम ट्यूब भी हैं जो वायरल के नमूनों को सूखने से और सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रदूषण से बचाती हैं। भारत-अमेरिका रणनीतिक भागीदारी एवं मंच के अध्यक्ष मुकेश अघी ने इस मदद के लिए कंपनी के प्रति आभार जताया।

यह कंपनियां मदद के लिए आईं आगे

अमेरिकन एयरलाइन्स ने कहा कि वह रेडक्रॉस के साथ मिल कर पूरी दुनिया में कोविड-19 से बचाव में लोगों की मदद कर रही है। कंपनी एमवे ने अमेरिकी वाणिज्य मंडल के नेतृत्व में काम कर रहे एक न्यास को 5 लाख डॉलर का चंदा दिया है। इससे भारत को 1000 वेंटिलेटर और 25,0000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेजी जाएंगी। कंपनी के मुख्य अधिशासी मिलिंद पंत ने कहा, 'एमवे के वैश्वि परिवार का मन-मस्तिष्क इस समय भारत पर लगा है।% डेविड एंड कैरॉल फेमिली फाउंडेशन ने भी ढाई लाख डॉलर की सहायता की घोषणा की है। अमेरिका इंडिया फाउंडेशन ने कहा कि उसे भारत में कोविड-19 चिकित्सा सुविधाओं में सहायता के लिए चुब चैरिटेबल फाउंडेशन से 5 लाख रुपए की मदद मिली है। इससे अस्पतालों को 100 सुविधाओं से सुसज्जित पोर्टेबल खाट उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर में नित नए मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अमेरिका की सरकार, कंपनियां और यहां के लोग भारत के लिए राहत सामग्री भेजने में बराबर जुटे हैं।

अमेरिका की 45 से अधिक बड़ी कंपनियां और उनके मुख्य अधिशासी अधिकारी अमेरिकी इस उद्देश्य से गठित एक कार्यबल में शामिल हैं।

25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1000 वेंटिलेटर भेजने की घोषणा

इसका गठन अमेरिकी वाणिज्य उद्योगमंडल और बिजनेस राउंडटेबल नाम के कंपनी संघों ने अमेरिका-भारत व्यावसायिक परिषद और अमेरिका-भारत रणनीतिक एवं भागीदारी मंच ने किया है। इस कार्यबल ने अब तक भारत को 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 1000 वेंटिलेटर भेजने की घोषणा की है। गूगल, डेलाइट, माइक्रोसाफ्ट, वॉलमार्ट, बोइंग और मास्टरकार्ड जैसे बड़े अमेरिकी व्यावसायिक प्रतिष्ठान भारत को कोविड सहायता भेजने में हाथ बंटा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय की सरकारी बैंकों को चेतावनी, कहा- Cairn कर सकती है उनके फंड को जब्त करने की कोशिश

बिजनेस डेस्क:

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को आगाह किया है कि वे उनके विदेशों में जमा धन को जब्त करने की ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी द्वारा किसी भी कोशिश के प्रति उच्च सतर्कता रखें। सूत्रों ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि भारत सरकार के साथ ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी के विवाद में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का निर्णय केयर्न के पक्ष में गया है। मध्यस्थता अदालत ने कंपनी पर भारत द्वारा पिछली तिथि से प्रभावी कानून संशोधन के माध्यम से लगाए गए कर को निरस्त कर दिया है और सरकार को केयर्न एनर्जी का 1.2 अरब डॉलर की राशि चुकाने का आदेश दिया था। केयर्न ने इससे पहले कहा था कि यदि उसे 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर और उस पर ब्याज तथा हर्जाने का भुगतान नहीं किया गया, तो वह विदेश में भारतीय परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए कानूनी कदम उठा सकती है। मध्यस्थता आदेश को लागू करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में पड़े भारतीय बैंकों की नकदी को आसान लक्ष्य माना जाता है। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने इस तरह की नकदी की रक्षा के लिए पीएसबी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा है ताकि केयर्न द्वारा किए गए ऐसे किसी भी प्रयास की तुरंत शिकायत की जा सके। इससे भारत सरकार परिसंपत्तियों को जब्त करने के खिलाफ कानूनी विकल्पों का सहारा ले सकेगी, क्योंकि बैंकों में जमा धन भारत सरकार का नहीं, बल्कि जनता का है। सूत्रों ने कहा कि इस मामले से निपटने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि बैंक अपने नास्ट्रो खाते में पर्याप्त धनराशि रख रहे हैं, ताकि व्यापार वित्त और अन्य विदेशी व्यवसायों की गतिविधि सुचारू रूप से जारी रहें। नोस्ट्रो खाता एक बैंक द्वारा विदेश के किसी बैंक में खोला गया खाता है, जहां उस देश की मुद्रा में धन रखा जाता है। ऐसे खातों का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए और विदेशी मुद्रा लेनदेन को निपटाने के लिए किया जाता है। मध्यस्थता अदालत ने भारत को ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी को 1.2 अरब डॉलर के साथ ब्याज और लागत को लौटाने का आदेश दिया गया है। भारत सरकार का तर्क है कि किसी सरकार द्वारा लगाया गया कर उसके सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र का विषय है जिसे निजी मध्यस्थता अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। केयर्न ने पूर्व में कहा था कि यह फैसला बाध्यकारी है और वह विदेशों में भारतीय संपत्तियों को जब्त कर इसका प्रवर्तन कर सकती है। केयर्न ने 1994 में भारत के तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश किया था। एक दशक बाद कंपनी ने राजस्थान में बड़ा तेल भंडार खोजा था। बीएसई में कंपनी 2006 में सूचीबद्ध हुई थी। 5 साल

बाद सरकार ने पिछली तारीख के कर कानून के आधार पर केयर्न से पुनर्गठन के लिए 10,247 करोड़ रुपए का कर मय ब्याज और जुर्माना अदा करने को कहा था। केयर्न ने इसे हेग में पंचाट न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। कंपनी की उसके बाद वित्त मंत्रालय के साथ इस भुगतान के लिए बातचीत चल रही है। कंपनी के अधिकारियों की तत्कालीन राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय के साथ फरवरी में तीन आमने-सामने की बैठकें हुई थीं। बाद में पांडेय के उत्तराधिकारी तरुण बजाज के साथ भी कंपनी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हो चुकी है।

महामारी संकट के दौरान TVS Motor ने किया ऐलान, करेगी 40 करोड़ रुपए की मदद

बिजनेस डेस्क:

दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर ने देश में जारी कोरोना संक्रमण के प्रकोप के संकट से निपटने के लिए 40 करोड़ रुपए की मदद देने की शुक्रवार को घोषणा की। कंपनी सुंदरम क्लेटन और समूह की दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर इसका प्रबंध कर रही है। इस धनराशि का इस्तेमाल देश भर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पीपीई किट, दवाइयां और अन्य चिकित्सा उपकरण मुहैया कराने में किया जाएगा। टीवीएस ने एक बयान में कहा कि वह तमिलनाडु, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तथा आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए प्रति दिन 20,000 से अधिक भोजन पैकेट का वितरण भी करेगी। साथ ही 500 से अधिक सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर 10 लाख से अधिक मास्क, कई हजार ऑक्सीमीटर, पीपीई किट समेत अन्य आवश्यक चिकित्सक उपकरणों भी प्रदान करेगी। टीवीएस मोटर के अध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन ने कहा, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से देश में हम अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। महामारी के गंभीर प्रभाव को कम करने के लिए हम इस स्थिति में एकजुट हो कर प्रयास करने चाहिए। टीवीएस मोटर ने इससे पहले पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान 60 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की थी। उसने कहा कि कंपनी ने पिछले एक वर्ष के दौरान बीस लाख से अधिक स्वास्थ कर्मियों को खाने के पैकेट और 10 लाख मास्क वितरित किए हैं।

कोविड मरीजों को सरकार ने दी बड़ी राहत, 2 लाख से ज्यादा का कर सकेंगे कैश पेमेंट

बिजनेस डेस्क:

सरकार ने कोविड-19 संक्रमण का इलाज करने वाले अस्पतालों, डिस्पेंसरी और कोविड केयर केंद्रों को मरीजों या उनके आश्रितों से 2 लाख रुपए से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है। यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी।

पैन या आधार कार्ड जरूरी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतान कर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के बीच संबंध की सूचना रखनी होगी। सीबीडीटी ने कहा, केंद्र सरकार यहां स्पष्ट करती है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्रों या कोविड मरीज का इलाज अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाली व्यक्ति का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतान करता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी।

नांगिया एलएलपी के भागीदार शैलेश कुमार ने कहा की वर्तमान परिस्थियों में कई अस्पताल और नर्सिंग होम कोवीड 19 के इलाज के लिए भुगतान नकद में मांगते है लेकिन आयकर कानून के तहत दो लाख से अधिक का भुगतान नकद में करने की अनुमति नहीं है।

प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर WhatsApp ने बदला फैसला, जानें क्या कहा कंपनी ने

बिजनेस डेस्क:

दिग्गज मैसेजिंग ऐप **WhatsApp** ने अपनी विवादित प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अहम ऐलान किया है। व्हाट्सऐप ने भारत में 15 मई से लागू होने वाली नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल टाल दिया है। कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी को लागू होने की नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है। कंपनी ने कहा कि नई पॉलिसी को स्वीकार ना करने वाला कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा। व्हाट्सऐप का सबसे बड़ा यूजर बेस भारत में ही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में उसके करीब 53 करोड़ यूजर हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने पीटीआई को भेजे ईमेल में लिखा है, 15 मई को किसी भी यूजर का अकाउंट इस वजह से डिलीट नहीं किया जाएगा कि उसने प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं की है। न ही भारत में किसी भी यूजर के व्हाट्सऐप की फंक्शनैलिटी पर इसका कोई असर पड़ेगा। हम अगले कई हफ्तों तक रिमाइंडर भेजकर फॉलोअप करेंगे।÷ हालांकि इसके साथ ही प्रवक्ता ने यह दावा भी किया है कि ज्यादातर यूजर्स ने नए टर्म्स ऑफ सर्विस यानी शर्तों को स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ लोगों ने अब तक ऐसा नहीं किया है। बहरहाल, कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि नई शर्तों को स्वीकार करने वाले यूजर्स कितने हैं। व्हाट्सऐप ने यह भी नहीं बताया है कि उसने 15 मई की डेडलाइन लागू नहीं करने का फैसला क्यों किया है।

पहले 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई की थी डेडलाइन

व्हाट्सऐप ने इससे पहले अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए यूजर्स को उसे स्वीकार करने के लिए 8 फरवरी तक का वक्त दिया था। उस वक्त भी कहा गया था कि व्हाट्सऐप को इस्तेमाल करने के लिए नई पॉलिसी को मंजूर करना जरूरी होगा लेकिन उस वक्त इसका काफी विरोध हुआ। ज्यादातर लोगों को आशंका थी कि उनका डेटा व्हाट्सऐप की पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा और फिर उसका व्यावसायिक इस्तेमाल होगा। भारी विरोध की वजह से ही कंपनी ने नई पॉलिसी स्वीकार करने की डेडलाइन फरवरी से आगे बढ़ाकर मई में कर दी थी।

कंपनी का दावा है कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने का यह मतलब नहीं है कि उसे यूजर्स के डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करने की ज्यादा छूट मिल जाएगी।

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा, कोविड-19 की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर रहेगा हल्का असर

बिजनेस डेस्क: वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर असर पहली लहर के मुकाबले हल्का ही रहेगा।

रिपोर्ट में हालांकि यह स्वीकार किया गया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट का जोखिम पैदा हुआ है।

दूसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने की उम्मीद

रिपोर्ट में कहा गया, पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर के अर्थवव्यस्था पर कम असर होने के कुछ कारण है। अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के साथ महामारी के साथ परिचालन की सीख से दूसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दूसरे चरण में आर्थिक गतिविधियों में सुधार से केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति बेहतर हुई है। वर्ष 2020-21 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में 4.5 प्रतिशत और 2019-20 की तुलना में 5 प्रतिशत ऊंचा रहा। यह कोरोना संक्रमण की पहली लहर के बाद से आर्थिक हालत में सुधार का संकेत देता है।

GST संग्रह में अच्छी वृद्धि

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी संग्रह में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले छह महीनों से जीएसटी का मासिक संगह एक लाख करोड़ रुपए से अधिक है। अप्रैल में यह 1.41 लाख करोड़ रुपए था जो एक कीर्तिमान है। यह अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार का संकेत है। रिपोर्ट में हालांकि यह भी माना गया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने बाजार का उत्साह प्रभावित किया है।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी- 50 और बीएसई का 30 शेयरों वाले सेंसेक्स क्रमशः 0.4 और 1.5 प्रतिशत नीचे आ गए हैं। इसी तरह अप्रैल में डॉलर के मुकाबला रुपया 2.3 प्रतिशत लुढ़क कर 74.51 तक आ गया।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

प्रसिद्ध कृष्णा कोरोना वायरस से संक्रमित, इंग्लैंड दौरे के लिए हुआ है चयन

बेंगलुरू। (एजेंसी)।

कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव मिलने के बाद बेंगलुरु स्थित अपने घर में पृथकवास पर है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने शनिवार को यह जानकारी दी। इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में 25 साल के प्रसिद्ध को स्टैंडबाई खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है। वह इस खतरनाक वायरस के चपेट में आने वाले केकेआर के चौथे खिलाड़ी है। बीसीसीआई के सूत्र ने कहा, ''प्रसिद्ध कोविड-19 पॉजिटिव है और फिलहाल बेंगलुरु स्थित अपने घर में पृथकवास पर है।''

उनसे पहले वरुण चक्रवर्ती, संदीप वारियर और टिम सीफर्ट केकेआर के उन खिलाड़ियों में शामिल है जो जांच में पॉजिटिव मिले है। बीसीसीआई सूत्र के मुताबिक प्रसिद्ध और वारियर एक अभ्यास सत्र के दौरान चक्रवर्ती से इस वायरस से संक्रमित हुए। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध और चक्रवर्ती अच्छे दोस्त है। सूत्र ने कहा, '' भारत के सभी खिलाड़ियों ने जांच में दो नेगेटिव परिणाम के साथ तीन मई को बायो-बबल (जैव सुरक्षित) छोड़ दिया था। वह हालांकि बेंगलुरु पहुंचने पर पॉजिटिव मिले।'' बीसीसीआई को उम्मीद है किब्रिटेन रवाना होने से पहले 25 मई को टीम के बायो-बबल में प्रवेश करने तक कृष्णा इस बीमारी से उबर जाएंगे।

न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट भी जांच में पॉजिटिव आने के बाद अहमदाबाद में पृथकवास में रहेंगे और फिर चेन्नई में निजी अस्पताल में उपचार करायेंगे। सीफर्ट का रवानगी से पहले दोनों आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है। उन में इस बीमारी के मामलू लक्षण है। बायो-बबल में कई खिलाड़ियों को सहयोगी सदस्यों के कोरोना पॉजिटव होने के बाद आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

टेस्ट के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने लगवाया कोरोना टीके का पहला डोज

मुंबई। (एजेंसी)।

भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस टीके का पहला डोज लगवा लिया है। 32 वर्ष के रहाणे न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिये भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान हैं।

रहाणे ने अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट किया ,''टीके का पहला डोज आज लगवा लिया। मैं सभी से रजिस्ट्रेशन करवाने और टीके लगवाने की अपील करता हूं।'' भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने गुरूवार को टीका लगवाया था। मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मार्च में टीका लगवा लिया था।

कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद करेंगे ऋषभ पंत

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी शनिवार को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गये और उन्होंने प्रभावित लोगों के लिये 'बेड' सहित ऑक्सीजन सिलेंडर तथा किट खरीदने के लिये अघोषित धनराशि देने का वादा किया। इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि वह गुरुग्राम स्थित गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) हेमकुंट फाउंडेशन को यह धनराशि दान करेंगे। पंत ने अपने ट्विटर पेज पर जारी बयान में कहा, ''मैं धनराशि के जरिये हेमकुंट फाउंडेशन की सहायता कर रहा हूं जो देश भर में पीड़ितों को बेड सहित ऑक्सीजन सिलेंडर, कोविड राहत किट और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराएगा।''

पंत ने पिछले एक साल से कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की मदद के लिये लगातार काम कर रहे लोगों की भी सराहना की। उन्होंने कहा, हालांकि इस बुरे दौर से पार पाने में भारत को हम सभी के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। मैंने किसी काम के लिये एक टीम के रूप में मिलकर काम करने की ताकत जैसा महत्वपूर्ण पहलू खेल से सीखा।

केविन पीटरसन की चाहत, इस देश में खेले जाएं आईपीएल 2021 के बचे हुए मुकाबले

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

आईपीएल 2021 के स्थगित होने के बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों के मन में यही सवाल है कि टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे। बचे हुए मैचों की मेजबानी करने के लिए इंग्लैंड की चार काउंटी टीमों ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा था, जबकि श्रीलंका ने भी आईपीएल को करवाने की इच्छा जताई है। हालांकि, बीसीसीआई ने इस पर अबतक कोई फैसला नहीं लिया है। इसी बीच, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन की चाहत है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के बचे हुए मैच इंग्लैंड में सितंबर में खेले जाएं।

पीटरसन का मामना है कि आईपीएल को ब्रिटेन में शिफ्ट करने का निर्णय सबसे अच्छा होगा, क्योंकि भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे पर पांच

मैचों की टेस्ट सीरीज 14 सितंबर को खत्म होगी और उसके बाद इसके लिए समय होगा। पीटरसन ने कहा, 'मैंने देखा है कि लोग सितंबर में आईपीएल के बचे हुए मैचों के आयोजन को यूएई में करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आयोजन इंग्लैंड में होना चाहिए।' पीटरसन ने 'बेटवे के लिए अपने कॉलम में लिखा, 'इंग्लैंड और भारत के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के बाद थोड़ा समय होगा। भारत के बेस्ट खिलाड़ी पहले से ही यहां होंगे, इसके साथ ही इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी उपलब्ध होंगे।'

दाएं हाथ के 40 साल के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि सितंबर में इंग्लैंड का मौसम क्रिकेट मैचों की मेजबानी के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा, 'सितंबर के बीच से आखिर तक इंग्लैंड का मौसम सबसे अच्छा रहता है। वह मैनचेस्टर, लीड्स, बर्मिंघम और लंदन के दो मैदानों का उपयोग कर सकते हैं। इस बात की भी अच्छी संभावना है कि वहां दर्शकों की मौजूदगी होगी। क्रिकेट के लिए यह शानदार होगा। आईपीएल का आयोजन यूएई और दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है और मुझे लगता है कि इसके बचे हुए मैचों के लिए इंग्लैंड सबसे बेहतर जगह होगी।'

आरसीबी के प्रदर्शन पर इरफान पठान बोले- बल्लेबाज से ज्यादा कप्तान के तौर पर खुश होंगे विराट कोहली

नई दिल्ली (एजेंसी)।

आईपीएल 2021 के स्थगित होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का प्रदर्शन इस सीजन शानदार रहा। टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में खेले 7 मुकाबलों में से 5 में जीत कर, जबकि 2 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली का बल्ला भले ही खामोश रहा, लेकिन उनके द्वारा कप्तानी में लिए गए फैसले एकदम सही साबित हुए। इसी बीच, भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि विराट एक बल्लेबाज से ज्यादा आरसीबी के कप्तान के तौर पर अपने प्रदर्शन से खुश होंगे। स्टार स्पोर्ट्स के शो पर बात करते हुए इरफान ने कहा, %अगर आप इस सीजन की बात करेंगे, विराट कोहली कप्तान ज्यादा खुश होंगे विराट कोहली बल्लेबाज की तुलना में। जिस तरह से पूरी टीम ने रिस्पॉड किया, जिस तरीके से विराट कोहली और माइक हेसन के कॉम्बिनेशन काम आए और जो उन्होंने ऑक्शन के समय में कड़ी मेहनत की। वह मैक्सवेल के लिए गए। ऑक्शन से पहले भी उन्होंने ट्रेडिंग के समय में भी काफी प्रयास किए थे। हमने हर्षल पटेल की बात की, लेकिन उन्होंने डैनियल सैम्स को भी शामिल किया, जिसका मतलब था कि उन्होंने सोचा कि अगर बेंगलुरु में खेलना का मौका मिला, तो डैनियस सैम्स काफी काम आएंगे। हालांकि, वह काम नहीं आए। हर्षल पटेल ने सभी काम कर दिया।' इरफान ने कहा कि जब आईपीएल को स्थगित किया गया, उस समय आरसीबी की फैन्स काफी निराश हुए होंगे। उन्होंने कहा, 'जहां पर टूर्नामेंट को रोका गया, वहां आरसीबी के फैन्स थोड़े बहुत निराश हुए होंगे, क्योंकि एबी डिविलियर्स अच्छी फॉर्म में थे, मैक्सवेल भी रन बना रहे थे, टीम काफी बढ़िया कर रही थी, गेंदबाजी में शानदार हो रही थी।

आशीष नेहरा ने बताया, इस वजह से पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में मिलने चाहिए ज्यादा मौके

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि इस खिलाड़ी ने अपनी तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि 21 साल के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को ज्यादा मौके देने चाहिए थे जब चीजें उनके मुताबिक नहीं हो रही थी। शॉ टीम इंडिया की तरफ से आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में खेले थे।जहां उनकी तकनीकी खामियां सामने आई थी।

एडिलेट टेस्ट में वो पहली पारी में जीरो और दूसरी पारी में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद बाकी टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया से उनकी छुट्टी हो गई थी। आशीष नेहरा ने कहा है कि ये काफी कठिन

फैसला था। नेहरा ने क्रिकबज से कहा कि जहां तक तकनीक का सवाल है किसी भी खिलाड़ी के लिए इसे एडजस्ट करना कठिन होता है। एडिलेट टेस्ट के दौरान वो ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसे 30 से 40 टेस्ट मैंच का अनुभव हो। हम एक युवा खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। एक टेस्ट मैच के आधार पर उसे ड्रॉप करना कठिन था।

इसके बाद पृथ्वी शॉ ने भारत आकर अपनी बल्लेबाजी पर काम किया। आईपीएल 14 से पहले खेली गई विजय हजारे ट्रॉफी में वो 800 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। आईपीएल 2021 में 8 मैचों में उन्होंने में 308 रन बनाए। आईपीएल 2020 में शॉ का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। शानदार अर्धशतकों से शुरुआत करने के बाद वो तीन बार जीरो पर आउट हुए। नेहरा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की तरह शॉ को दिल्ली कैपिटल्स ने ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, खासकर उनके सीनियर अजिंक्य रहाणे के लिए। रहाणे ने दो मैचों में 8 रन बनाए थे।

नेहरा ने कहा कि भले ही भारत सीरीज जीतने के लिए गया था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसे एक टेस्ट के बाद बैंच पर नहीं बैठाना चाहिए था। पिछले साल आईपीएल में भी उसे नहीं बैठाना चाहिए था, जब उसने कुछ अच्छी पारियां खेली और स्कोर नहीं कर सके। लेकिन अगर आप टी20 की बात करेंगे तो मैं हमेशा ऐसे खिलाड़ी को सपोर्ट करूंगा जिसके खाते में रहाणे से अधिक रन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रहाणे अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन टी 20 में आपको शॉ, पंत, हेटमायर और स्टोइनिस जैसे विस्फोटक खिलाड़ियो की जरूरत है।

न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सीफर्ट कोरोना पॉजिटिव, चेन्नई में कराएंगे उपचार

जोहानिसबर्ग। (एजेंसी)।

क्राइस्टचर्च। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अन्य खिलाड़ियों तथा सहयोगी स्टाफ के साथ चार्टर्ड उड़ान से लौट नहीं सकेंगे। वे अहमदाबाद में क्वारंटाइन में रहेंगे और फिर चेन्नई में निजी अस्पताल में उपचार कराएंगे। सीफर्ट का रवानगी से पहले दोनों आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड व्हाइट ने कहा कि सीफर्ट के पिछले 10 दिन में 7 टेस्ट नेगेटिव आए थे। उन्होंने यकीन जताया कि उनकी टीम उनका पूरा ख्याल रखेगी। उन्होंने कहा कि टिम के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम अपनी ओर से उसकी पूरी मदद करेंगे। उम्मीद है कि उसका टेस्ट जल्दी ही नेगेटिव आएगा और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

उन्होंने कहा कि खबर मिलने के बाद से हम खिलाड़ियों के संघ के मार्फत उसके लिए मदद जुटा रहे हैं। हम उसके परिवार के संपर्क में हैं और उन्हें पूरी जानकारी दी जा रही है। क्वारंटाइन पूरा होने और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वह न्यूजीलैंड रवाना होंगे, जहां 14 दिन फिर क्वारंटाइन में रहेंगे।

न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को लेकर एक चार्टर्ड उड़ान रवाना हो चुकी है और दूसरी आज शनिवार शाम जाएगी। इन उड़ानों से जा रहे सभी व्यक्ति कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करेंगे। उनकी ऑकलैंड पहुंचने के बाद फिर जांच की जाएगी। सीफर्ट को चेन्नई के उसी अस्पताल में रखा जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइक हसी इलाज करा रहे हैं।

ब्रिटेन जाने वाले न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, मिशेल सेंटनेर, काइल जैमिसन और फिजियो टॉमी सिमसेक दिल्ली में रुकने की बजाय मालदीव चले गए हैं। न्यूजीलैंड के ट्रेनर क्रिस डोनाल्डसन भी मालदीव गए हैं, जो पहले न्यूजीलैंड जाना चाहते थे। इस दल को मालदीव भेजने का फैसला इसलिए लिया गया कि उनकी ब्रिटेन रवानगी में 1 हफ्ता विलंब हो सकता है। पहले लगा था कि वे 11 मई को ब्रिटेन रवाना हो जाएंगे।

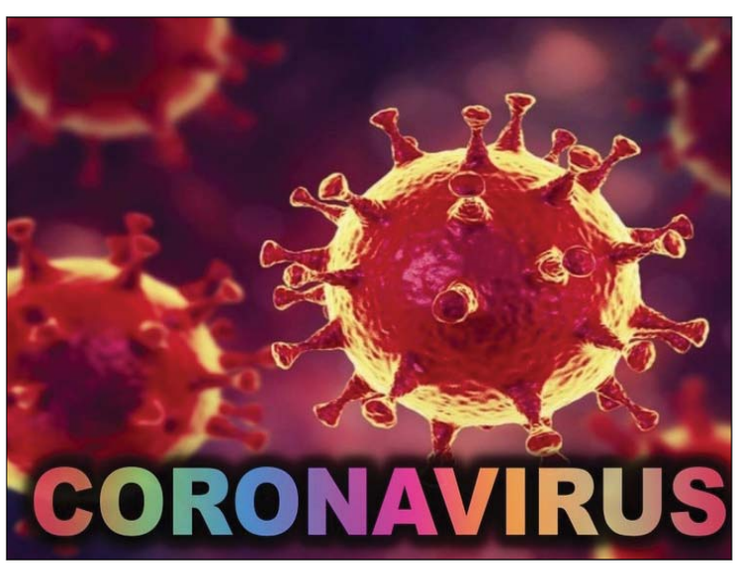

कप्तान रानी और भारतीय महिला हॉकी टीम की छह सदस्यों ने दी कोविड-19 को मात

नयी दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी की कप्तान रानी रामपाल और टीम की उनकी छह अन्य साथियों के साथ दो सहायक सदस्य बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) केन्द्र में दो सप्ताह तक पृथकवास पर रहने के बाद कोविड-19 के संक्रमण से उबर गए हैं। रानी के अलावा सविता पूनिया, शर्मिला देवी, रजनी, नवजोत कौर, नवनीत कौर और सुशीला के साथ कोरोना वायरस के चपेट में आने वालों में टीम के वीडियो विश्लेषक अमृतप्रकाश और वैज्ञानिक सलाहकार वेन लोम्बार्ड शामिल थे। इन सातों खिलाड़ियों को 10 दिनों के ब्रेक के बाद बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में भारतीय महिला हॉकी कोर ग्रुप की वापसी के बाद 24 अप्रैल को जांच में पॉजिटिव पाया गया था। उनमें हालांकि इस बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे थे। रानी ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा, '' पिछले दो सप्ताहों के दौरान संदेशों / फोन कॉल के माध्यम से प्यार और मानसिक समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं, टीम की मेरी साथी और सहयोगी कर्मचारी कोविड-19 से अब पूरी तरह उबर गये है।'' उन्होंने कहा, '' हॉकी बिरादरी के सदस्यों / मित्रों / प्रशंसकों के तौर पर आप सब के होने से मैं खुद को धन्य मानती हूं। हमारी अच्छी देखभाल करने के लिए हॉकी इंडिया और साइ को विशेष धन्यवाद।'' रानी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे इन कठिन समय में जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें। उन्होंने कहा, '' इस बारे में जानकर बहुत दुख हो रहा कि इतने सारे लोग अपने प्रियजनों को खो रहे है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं। कृपया अपने निकट और प्रियजनों की जितना हो सके उतनी मदद करें।'' उन्होंने कहा, ''आइए मिलकर इस महामारी से लड़ें। सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और कोविड-19 से जुड़ी सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।

तुर्की में यात्रा प्रतिबंधों के कारण इंग्लैंड में हो सकता है चैम्पियंस लीग फाइनल

लंदन। चैम्पियंस लीग फुटबॉल फाइनल इंग्लैंड में ही हो सकता है क्योंकि मेजबान तुर्की भी इंग्लैंड की 'रेड लिस्ट' वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां कोरोना महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंध लागू होंगे। चेलसी और मैनचेस्टर सिटी को 29 मई को इस्तांबुल में खेलना था।

युएफा को उम्मीद थी कि यूरोपीय फुटबॉल सत्र के इस सबसे बड़े मैच को देखने करीब दस हजार दर्शकों को अनुमति मिल जायेगी। ब्रिटिश सरकार ने शुक्रवार को नये यात्रा प्रतिबंध लागू करकेलोगों को तुर्की नहीं जाने की सलाह दी है।इसने यह भी कहा कि इंग्लिश फुटबॉल संघ चैम्पियंस लीग आयोजक युएफा से बात कर रहा है ताकि मैच ब्रिटेन में ही हो सके।

मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी रविंदर पाल सिंह का कोरोना से निधन

नयी दिल्ली। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य और मॉस्को ओलंपिक 1980 के स्वर्ण पदक विजेता रविंदर पाल सिंह ने करीब दो सप्ताह कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शनिवार की सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली। वह 65 वर्ष के थे। सिंह को 24 अप्रैल को विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वह कोरोना संक्रमण से उबर चुके थे और टेस्ट नेगेटिव आने के बाद कोरोना वॉर्ड से बाहर थे। शुक्रवार को उनकी हालत अचानक बिगड़ी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। लॉस एंजिलिस ओलंपिक 1984 खेल चुके सिंह ने विवाह नहीं किया था। उनकी एक भतीजी प्रज्ञा यादव है। वह

1979 जूनियर विश्व कप भी खेले थे और हॉकी छोड़ने के बाद स्टेट बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली थी। सीतापुर में जन्में सेंटर हाफ सिंह ने 1979 से 1984 के बीच शानदार प्रदर्शन किया। दो ओलंपिक के अलावा वह 1980 और 1983 में चैम्पियंस ट्रॉफी , 1982 विश्व कप और 1982 एशिया कप भी खेले।

निशानेबाज राही सरनोबत बोलीं- मैं दबाव में बेहतर प्रदर्शन करती हूं...

नई दिल्ली। अपने दूसरे ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहीं भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने कहा कि वे टूर्नामेंटों में दवाब में रहना पसंद करती हैं, क्योंकि इससे वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं। सरनोबत भारत के उस 15 सदस्यीय दल में शामिल हैं, जो 11 मई को जगरेब और फिर वहीं से टोक्यो खेलों के लिए रवाना होगा। विश्व कप और एशियाई कप में स्वर्ण पदक जीतने वालीं सरनोबत ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा, मुझे लगता है कि मैं दबाव में बेहतर प्रदर्शन करती हूं। मुझे इससे जिम्मेदारी का अहसास होता है और खुद से अधिक की उम्मीद होती है। एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज ने कहा, मैं वास्तव में दबाव में रहने का

लुत्फ उठाती हूं, क्योंकि इससे अपना सर्वश्रेष्ठ कर पाती हूं।उन्होंने कहा कि 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी में पहले के प्रदर्शन ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। जर्मनी के कोच मुंखबायर दोरज्सुरेन के जाने के बाद सरनोबत हाई परफॉर्मेंस कोच समरेश जंग की देखरेख में अभ्यास कर रही हैं। समरेश हालांकि भारतीय टीम के साथ क्रोएशिया दौरे पर नहीं जाएंगे जहां टीम को यूरोपीय चैंपियनशिप (20 मई से 6 जून) और आईएसएसएफ विश्व कप (22 जून से 3 जुलाई) में भाग लेना है। सरनोबत ने कहा कि यह उनके लिए हालांकि चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अपने जर्मन कोच के साथ काम कर रही थी, लेकिन पिछले साल ओलंपिक के स्थगित होने से उनका अनुबंध समाप्त हो गया। फिर मैंने समरेश भैया से बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा, अगर वे वहां नहीं रहेंगे तो भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यह वास्तव में अलग तरह की स्थिति है। हमें सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा, हमें अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

नेपाल में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने से जरूरी चिकित्सकीय सामानों की किल्लत

काठमांडू। नेपाल में कोविड-19 रोधी टीकों और जरूरी चिकित्सकीय सामानों की घोर किल्लत हो गयी है। वहीं विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के मामलों में अचानक वृद्धि से अस्पतालों में बिस्तर और चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कमी से बड़ा संकट पैदा होने को लेकर आगाह किया है। नेपाल में 21 लाख लोगों को अब तक टीके की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। हालांकि, दोनों खुराक चार लाख से कम लोगों को ही मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 'सीरम इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया' ने उत्पादन इकाई में आग लगने से टीकों की आपूर्ति करने में असमर्थता जतायी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों में किए गए दावों को खारिज कर दिया कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार से टीकों की 50 लाख अतिरिक्त खुराकें खरीदने वाली है। काठमांडू में संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉ. अशोक कर्की ने कहा कि मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में तेजी से बिस्तर और ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। नेपाल में शुक्रवार को कोविड-19 के 9023 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 377,603 हो गयी। पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की मौत से अब तक 3,579 लोग दम तोड़ चुके हैं।

अमेरिकी सर्जन जनरल ने मंदिरों को कोविड-19 टीकाकरण केंद्र बनाने की सराहना की

वाशिंगटन। अमेरिका के सर्जन जरनल डॉ. विवेक मूर्ति ने अपने मंदिरों को कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में बदलने के लिए भारतीय-अमेरिकी परमार्थ संगठन 'बीएपीएस चैरिटीज' की सराहना की। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) के अमेरिका में 100 से अधिक केंद्र हैं। मूर्ति ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''मैं भारतीय-अमेरिकी संगठन बीएपीएस चैरिटीज पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसने अपने मंदिरों को टीकाकरण केंद्र में बदल दिया है।'' उन्होंने कहा, ''इन मंदिरों के बुजुर्ग सदस्यों के लिए किसी अपरिचित स्थान के बजाए अपने मंदिर में अपने परिवार और विश्वसनीय मित्रों के बीच टीकाकरण कराना आसान है।

नेपाली पर्वतारोही ने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर बनाया रिकॉर्ड

काठमांडू। नेपाल के 52 वर्षीय पर्वतारोही ने शुक्रवार को 25वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पर्वतारोहण के इस अभियान का आयोजन करने वाले 'सेवन समिट ट्रेक्स' के अध्यक्ष मिंगमा शेरपा ने कहा कि कामी रीता शेरपा ने 11 अन्य शेरपा का नेतृत्व करते हुए इस अभियान की शुरुआत की। यह दल शुक्रवार शाम को सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गया। कामी 2019 में 24वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। 2019 में उन्होंने एक महीने में ही दो बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने की कामयाबी हासिल की थी। कामी ने मई 1994 को पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। 1994 से 2021 के बीच वह 25 बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे। उन्होंने के2 और माउंट ल्होत्से पर एक-एक बार, माउंट मनासलु पर तीन बार और माउंट चो ओयु पर आठ बार चढ़ाई की है।

मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में हिन्दू महिला रामचंद ने किया कमाल, पास की प्रतिष्ठित सीएसएस की परीक्षा

नई दिल्ली। पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू महिला ने देश की प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज (सीएसएस) परीक्षा पास की है और विशिष्ट पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा (पीएएस) के लिये चयनित हुई है। पाकिस्तान के सर्वाधिक हिंदू आबादी वाले सिंध प्रांत के शिकारपुर जिले के ग्रामीण इलाके की रहने वाली सना रामचंद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। वह सीएसएस की परीक्षा पास करने वाले 221 अभ्यर्थियों में शामिल हैं। 18,553 परीक्षार्थियों ने यह लिखित परीक्षा दी थी। विस्तृत चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और मौखिक परीक्षा के बाद अंतिम चयन किया गया। मेधासूची निर्धारित होने के बाद अंतिम चरण में समूह आवंटित किये गए।

परिणाम घोषित होने के बाद रामचंद ने ट्वीट किया, 'वाहे गुरू जी का खालसा वाहे गुरू जी की फतेह'। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है अल्लाह के फजल से मैंने सीएसएस 2020 की परीक्षा पास कर ली है और पीएएस के लिए मेरा चयन हो गया है। इसका पूरा श्रेय मेरे माता-पिता को जाता है।'

हालिया सीएसएस परीक्षा में पास प्रतिशत दो से भी कम है जो कड़ी प्रतिस्पर्धा और के साथ ही इन परीक्षा का संचालन करने वाले संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किये गए कड़े मानकों को भी दर्शाता है। पीएएस शीर्ष श्रेणी है जिसके बाद अक्सर पाकिस्तान पुलिस सेवा और पाकिस्तान विदेश सेवा तथा अन्य आते हैं। पीएएस श्रेणी हासिल करने वालों को सहायक आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया जाता है और बाद में प्रोन्नत होकर वे जिला आयुक्त बनते हैं जो जिलों का नियंत्रण करने वाला शक्तिशाली प्रशासक होता है।

बीबीसी उर्दू की खबर के अनुसार रामचंद पहली हिंदू महिला हैं, जिनका सीएसएस परीक्षा के बाद पीएएस के लिए चयन हुआ है। अंतिम सूची में 79 महिलाएं शामिल हैं और उन्हें पीएएस समेत विभिन्न समूह आवंटित हुए हैं। परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने वाली भी एक महिला, माहीन हसन, हैं जिन्हें पीएएस आवंटित किया गया है।

सऊदी की शरण में फिर पहुंचा कर्ज तले दबा पाकिस्तान, 3 दिन की यात्रा पर गए इमरान खान, जानें मकसद

नई दिल्ली (एजेंसी)।

रिश्तों में तल्खी के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सऊदी अरब की यह यात्रा नाराज क्राउन प्रिंस को मनाने के रूप में देखी जा रही है। शुक्रवार को जब इमरान खान सऊदी अरब पहुंचे तो जेद्दाह एयरपोर्ट पर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी आगवानी की। अपनी इस तीन दिनों यात्रा के दौरान इमरान खान अरब देश के शीर्ष नेतृत्व से द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों पर वार्ता करेंगे। दोनों मुल्क रिश्तों में हाल आए तनाव के बाद इन्हें ठीक करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

यात्रा के पहले दिन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और सऊदी अरब ने दोनों देशों के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग का वादा भी किया और समझौतों पर दस्तखत किया। माना जा रहा है कि इमरान खान अपनी इस यात्रा से सऊदी के साथ अपने संबंधों को फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इमरान खान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्यौते पर वहां गए हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री और कैबिनेट के अन्य सदस्य शामिल हैं।

माना जा रहा है कि सऊदी नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री इमरान की बातचीत आर्थिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, पाकिस्तानी कामगारों के लिए नौकरी, वहां पर रह रहे पाकिस्तानी प्रवासियों के कल्याण समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों को कवर करेगी। इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है।

इस यात्रा के दौरान इमरान खान 'इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के महासचिव यूसुफ अल ओसैमीन, वर्ल्ड मुस्लीम लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा और मक्का तथा मदीना की दो पवित्र मस्जिदों के इमामों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ रिश्तों में 2015 में तब तनाव आ गया था जब पाकिस्तान ने यमन में सऊदी जंग के लिए सैनिक भेजने से मना कर दिया था। यह भी माना जाता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और भारत के बीच गहरे होते रिश्तों से खुश नहीं है।

सऊदी के कर्ज तले दबा है पाकिस्तान

सऊदी अरब ने इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद साल 2018 में पाकिस्तान को 6.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। सऊदी अरब द्वारा घोषित 6.2 बिलियन डॉलर के कर्ज वाले पैकेज में कुल 3 बिलियन डॉलर का कर्ज और 3.2 बिलियन डॉलर की एक ऑयल क्रेडिट की सुविधा शामिल थी।

कुरैशी ने किया था सऊदी को नाराज

कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की बैठक बुलाने में सऊदी अरब का समर्थन नहीं मिलने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की बौखलाहट सामने आई थी। पाक विदेश मंत्री कुरैशी ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी बैठक आयोजित नहीं करने को लेकर धमकाया था और इसकी सऊदी की आलोचना की थी। इतना ही नहीं, कुरैशी ने मुस्लिम देशों के इस संगठन को तोड़ने की भी धमकी दी थी। पाकिस्तान के एक लोकल न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा था, 'मैं एक बार फिर से पूरे सम्मान के साथ इस्लामिक सहयोग संगठन से कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक हमारी अपेक्षा है। अगर आप इसे बुला नहीं सकते हैं तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से यह कहने के लिए बाध्य हो जाऊंगा कि वह ऐसे इस्लामिक देशों की बैठक बुलाएं, जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और जो दबाए गए कश्मीरियों का साथ देते हैं।'

बुखार न आए तब भी बुजुर्गों को हो सकता है कोरोना, कैसे करें पहचान? जानें नई स्टडी में क्या खुलासा हुआ

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

कोरोना की दूसरी लहर में बुखार आने का मतलब कोरोना पॉजिटिव होना मान लिया गया है। युवाओं पर यह बात काफी हद तक सही साबित हो रही है पर बुजुर्गों के मामले में बुखार वाली थ्योरी ठीक नहीं है। एक ताजा शोध के अनुसार, जरूरी नहीं कि बुजुर्गों को कोरोना होने पर बुखार आए। तो फिर बुजुर्गों में शुरुआत में कोविड-19 संक्रमण की पहचान कैसे हो? इसका जवाब है कि पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर लगातार उनके ऑक्सीजन स्तर पर नजर रखी जाए। सिर्फ बुखार को प्रमुख लक्षण मानकर उसकी मॉनिटरिंग करने से न केवल उनकी जान को खतरा हो सकता है बल्कि परिवार के दूसरे सदस्य भी संक्रमित हो सकते हैं।

अमेरिका की वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में कोरोना पर हुए नए शोध के अनुसार, वृद्ध जनों के मामले में शरीर के तापमान की जांच करने की बजाय पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल ज्यादा कारगर है। ताजा शोध मेडिकल जर्नल फ्रंटियर्स इन मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। इसे वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की कैथरीन वान सोन और डेबोरा इती ने किया है।

बाकी सभी लक्षण दिखे

शोधकर्ताओं के अनुसार, गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित 30 प्रतिशत बुजुर्गों को बिल्कुल बुखार नहीं आया या बेहद कम आया। हालांकि, उनमें कोरोना के अन्य लक्षण जैसे थकान, बदन दर्द, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता का गायब होना आदि दिखे।

ऑक्सीजन स्तर पर रखें नजर

इसीलिए वैज्ञानिकों ने बुजुर्गों के मामले में शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी (हाइपोक्सिया) को पल्स ऑक्सीमीटर से पहचानने की सलाह दी है। इसके बाद आरटी-पीसीआर जांच से कोरोना की पुष्टि हो सकती है।

ऑक्सीमीटर लगाते वक्त बरतें सावधानी

-ऑक्सीमीटर को उंगली पर लगाते वक्त हाथ गर्म और आराम से रखें

-जिस उंगली पर ऑक्सीमीटर लगाना हो उससे नेल पॉलिश आदि हटा लें

-ऑक्सीजन स्तर समय-तारीख के साथ नोट करें और बदलाव को समझें

-रीडिंग स्थिर होने तक कुछ समय के लिए ऑक्सीमीटर को लगा रहने दें

रीडिंग पर इन बातों का भी पड़ता है असर

-कमजोर ब्लड सर्कुलेशन

-त्वचा की मोटाई

-तंबाकू आदि का इस्तेमाल

-चमड़ी पर दाग-धब्बे आदि का होना

-उंगलियों पर स्याही या नेल पॉलिश होने से

-त्वचा का तापमान

अमेरिका के भारतीय-अमेरिकी डॉक्टर 5,000 ऑक्सीजन सांद्रक भेज रहे हैं भारत

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

डॉक्टरों का एक भारतीय-अमेरिकी समूह कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए भारत में 5,000 ऑक्सीजन सांद्रक भेज रहा है। हाल ही में बनी 'फेडरेशन ऑफ इंडियन फिजिशियंस एसोसिएशन' (एफआईपीए) ने शुक्रवार को कहा कि 5,000 ऑक्सीजन सांद्रक खरीद लिए गए हैं। इनमें से 450 ऑक्सीजन सांद्रक पहले ही अहमदाबाद पहुंच गए हैं, 325 दिल्ली भेजे जा रहे हैं और 300 ऑक्सीजन सांद्रक मुंबई भेजे जा रहे हैं। एफआईपीए के अध्यक्ष डॉ. राज भयानी ने कहा, ''ये ऑक्सीजन सांद्रक स्थानीय भारतीय साझेदारों, अस्पतालों, अस्थायी पृथकवास केंद्रों, नव निर्मित अस्थायी अस्पतालों और परमार्थ संगठनों को भेजे जाने हैं ताकि भारत में दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थानीय साझेदार जरूरत पड़ने पर कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकें।'' उन्होंने कहा कि करीब 3,500 और ऑक्सीजन सांद्रक भेजे जाने हैं। एफआईपीए ने इन ऑक्सीजन सांद्रकों को फौरन भेजे जाने में मदद के लिए भारतीय दूतावास और भारत के उड्डयन मंत्रालय से बात की है। भारत के ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले आयोवा स्थित सहगल फाउंडेशन ने एक अलग बयान में कहा कि वह भारत को 200 ऑक्सीजन सांद्रक भेज रहा है। भारतीय-अमेरिकी वंदना कर्ण ने ग्रामीण बिहार में लोगों की जान बचाने के लिए शनिवार को रकम जुटाने के वास्ते एक अभियान शुरू की। महज कुछ ही घंटों में 8,000 डॉलर से अधिक धनराशि जुटा ली गई।

नासा ने जारी की मंगल ग्रह से अपने हेलीकॉप्टर की आवाज, क्या आपने सुनी यह ऑडियो क्लिप?

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने मंगल पर भेजे गए अपने हेलीकॉप्टर की शानदार तस्वीरें और वीडियो साझा करने के बाद लाल ग्रह पर उसकी आवाज जारी की है, जो मच्छर के भिनभनाने की आवाज की तरह प्रतीत होती है। नासा की कैलिफोर्निया स्थित 'जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी' ने शुक्रवार को 'इन्जेनुइटी हेलीकॉप्टर' की पांचवीं परीक्षण उड़ान भरने से पहले अब तक की पहली ऑडियो क्लिप जारी की। एक सप्ताह पहले चौथी उड़ान के दौरान 2,500 परिक्रमण प्रति मिनट की गति से घूमने वाले हेलीकॉप्टर के ब्लेड की आवाज बहुत धीमी थी। यह किसी मच्छर के भिनभिनाने जैसी आवाज प्रतीत होती है। इसका कारण है कि चार पाउंड (1.8 किलोग्राम) वजनी यह हल्का हेलीकॉप्टर पर्सिवरेंस रोवर के माइक्रोफोन से 260 फुट से अधिक दूरी पर था। वैज्ञानिकों ने ब्लेड के घूमने की आवाज को अलग करके उसे बढ़ाया, ताकि उसे सुना जा सके। नासा के प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर ने 19 अप्रैल को धूलभरी लाल सतह से पहली उड़ान भरी थी और किसी अन्य ग्रह पर पहली नियंत्रित उड़ान की उपलब्धि हासिल की। नासा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ऑडिया जारी किया है। इस घटनाक्रम की तुलना राइट ब्रदर्स के प्रयोग से की जा रही है। इन्जेनुइटी हेलीकॉप्टर ने 1903 के राइट फ्लायर के सरीखे विंग फैब्रिक के साथ उड़ान भरी। राइट फ्लायर ने उत्तर कैरोलिना के किटी हॉक में ऐसा ही इतिहास रचा था। हेलीकॉप्टर ने शुक्रवार को 108 सेकंड की उड़ान भरी। इन्जेनुइटी ने फरवरी में मंगल के लिए उड़ान भरी थी।

इराक में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला

बगदाद। इराक में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति वाले सैन्य ठिकानों पर शनिवार तड़के ड्रोन से हमला किया गया। इराकी सेना और अमेरिका नीत गठबंधन सेना ने हालांकि स्पष्ट किया है कि इस हमले में मामूली नुकसान हुआ है और कोई हताहत नहीं हुआ है। गठबंधन सेना के प्रवक्ता कर्नल वेयने मारोट्टो ने ट्वीट कर बताया कि तड़के किए गए हमले से हैंगर को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमले की जांच की जा रही है। इराकी सेना ने भी अपने बयान में कहा कि किसी नुकसान की खबर नहीं है। इस हमले की अबतक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हुए हमलों के लिए अमेरिका, ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराता रहा है,लेकिन पूर्व में अधिकतर रॉकेट हमलों से बगदाद और देश के अन्य सैन्य हिस्सों में अमेरिकियों को निशाना बनाया गया था। ड्रोन हमले बहुत आम नहीं है। अप्रैल के मध्य में विस्फोटक लदे ड्रोन ने इरबिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सैन्य हिस्से को निशाना बनाया था।

कोविड-19 से निपटने में भारत की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार ने कहा है कि अमेरिका सरकार कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित भारत की इस संकट से निपटने में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मंत्रालय के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ सलाहकार एर्विन मासिंगा ने कहा कि भारत में हवाई मार्ग से छह खेप भेजी गई हैं, जिनमें ऑक्सीजन सांद्रक, एन95 मास्क, त्वरित जांच के लिए किट और दवाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने करीब 10 करोड़ डॉलर की सहायता दी है।

मासिंगा ने 'भारत में अमेरिका के कोविड-19 राहत प्रयास बढ़ाना- समुदाय का नजरिया' विषय पर आयोजित समारोह में कहा, ''पूरी अमेरिकी सरकार- (अमेरिका के) राष्ट्रपति जो बाइडन से लेकर दूतावास और महावाणिज्य दूतावास की टीमें- भारत की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं।'' इस बीच, भारतीय अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने भारत के लिए निधि एकत्र करने की अपील की है। जयपाल ने शुक्रवार को कहा, ''भारत को हमारी मदद की आवश्यकता है और इस चुनौती से निपटने में मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यह वैश्विक महामारी है और जब तक इस वायरस को हर जगह से समाप्त नहीं कर दिया जाता, जब तक हम पूरी तरह उबर नहीं सकते।

दक्षिण अफ्रीका में हिंदू और मुस्लिम शादियों के कानूनी दर्जे पर हुई चर्चा

जोहानिसबर्ग। (एजेंसी)।

दक्षिण अफ्रीका में हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से हुई शादियों में पति-पत्नियों के सामने आ रही मुश्किलों पर 'ग्रीन पेपर' में विचार किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के एक से ज्यादा पति होने के विवादित मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है। इस ग्रीन पेपर को अगले महीने के अंत तक जनता की टिप्पणियों के लिए जारी किया गया है। विभिन्न पक्षकारों से महीनों तक व्यापक चर्चा करने के बाद यह पत्र तैयार किया गया है। गृह मामलों के विभाग (डीएचए) ने 'ग्रीन पेपर' में कहा, ''मुस्लिम, हिंदू और यहूदी शादियों को मान्यता देने का मुद्दा उठा। पक्षकारों ने विधायी माध्यमों से इन शादियों को मान्यता देने की तत्काल आवश्यकता का मुद्दा उठाया।'' इसमें कहा गया है, ''पहले की विसंगतियों को खत्म करने के प्रयासों के बावजूद मौजूदा विवाह कानूनों में कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों की शादियों को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है।'' इसमें कुछ अफ्रीकी समुदायों में हुई इस्लामी और हिंदू शादियां शामिल हैं और साथ ही ट्रांसजेंडरों की शादियां भी शामिल हैं। मौजूदा विवाह कानून के तहत हिंदू, मुस्लिम तथा अन्य धार्मिक विवाह अधिकारी शादियां करा सकते हैं, लेकिन शादी डीएचए में पंजीकृत भी होनी चाहिए क्योंकि धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ की गई शादी की कोई कानूनी वैधता नहीं है। डीएचए ने कहा, ''चर्चा में बहुविवाह का मुद्दा भी विवादित रहा। कुछ पक्षकारों ने बहुविवाह प्रथा में विश्वास जताया जबकि कुछ ने इसका विरोध किया।''पक्षकारों के साथ बाचतीत में यह खुलासा हुआ कि अदालतों ने मुस्लिम शादियों में पति/पत्नियों को विवाह संबंधित कई अधिकार दिए हैं जबकि हिंदू और अन्य धर्मों के लोगों को कम अधिकार दिए गए हैं जिससे इन धार्मिक शादियों के पास मुस्लिमों की शादियों के मुकाबले कम और कमजोर अधिकार हैं। डीएचए ने कहा कि हिंदू शादियों में तलाक एक कलंक है जो महिलाओं को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ देता है। कानून में ऐसी शादियों को संरक्षण नहीं दिया गया है, जिससे स्थिति जटिल हो जाती है। इन सब मुद्दों से निपटने के लिए ग्रीन पेपर में सभी मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों के संरक्षण के वास्ते नए विवाह कानूनों के लिए तीन विकल्पों का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें मौजूदा विवाह कानून में संशोधन, एक विवाह या बहुविवाह को मान्यता देना शामिल हैं।

डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, पाबंदी में ढील दी गयी तो गहरा सकता है महामारी का संकट

जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के विभिन्न स्वरूपों के कारण मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तथा साथ ही, देशों को आगाह किया कि प्रभावी कदम में जरा भी ढील से महामारी की स्थिति और गंभीर हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आपात सेवा प्रमुख डॉ माइकल रेयान ने कहा कि वायरस तेजी से एक से दूसरे देश में फैलता है और जो नेता सोचते हैं कि टीकाकरण से ही महामारी खत्म हो जाएगी तो वे गलती कर रहे हैं। रेयान ने कहा, ''यह मानवीय व्यवहार, वायरस के नए-नए स्वरूप के उभरने और कई अन्य पहलुओं पर निर्भर करता है।'' उन्होंने कुछ नेताओं से स्थिति की ''भयावह वास्तविकता'' को स्वीकार करने के लिए कहा। भारत में भी संक्रमण और मौतों की संख्या बढ़ी है। रेयान ने कहा, ''कुछ देश अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आपको अपने स्वास्थ्य ढांचे की रक्षा करनी चाहिए। आपको ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल करनी चाहिए।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मदर्स डे पर विशेष

घर की पाठशाला की पहली गुरु

मां को गुरु दर्जा यों ही नहीं मिला। बच्चों को अनुशासन का पहला पाठ वही तो पढ़ाती है। नवजात के जन्म से लेकर नर्सरी में जाने तक मां वस्तुतः एक आदर्श पुरुष या नारी को ही तैयार कर रही होती है। अक्षर ज्ञान से लेकर रंगों का ज्ञान, प्रकृति से रूबरू कराने से लेकर अपने आसपास के बारे में इस तरह बताती-सिखाती चलती है कि बच्चा जब घुटनों के बल खड़ा होता है या दौड़ता है तो वह अपनी मां की नसीहतों को अवचेतन में रखता है। नसीहत देने की आदत मांओं की पुरानी आदत रही है। अब इसमें भी बदलाव आया है। हालांकि बेटियां आज भी अपनी मां से सलाह लिए बिना कभी कोई कदम नहीं उठाती। मगर बेटे अब बदल रहे हैं।

अपने बच्चों को हमेशा पलकों की छांव में रखने वाली मां आज भी यही चाहती है कि उसके बच्चों पर किसी बुरे व्यक्ति का साया न पड़े। उसे अपने आंचल में छुपा कर रखती है। बच्चों को अच्छे-बुरे का पहला ज्ञान तो वही देती है।

बच्चों की आकांक्षाओं को

उड़ान देती सुपर मॉम

बदल रही है मां की भूमिका

बच्चों को अपने आंचल से बांधे रखने का दौर अब खत्म हो चुका है। ज्यादातर आधुनिक मांएं इस बात को समझ चुकी हैं कि नसीहत देने से अच्छा है कि बच्चों की वे मार्गदर्शक बनें। वे अपने बेटे-बेटियों को ज्ञान के पंख देकर उन्हें उड़ान भरने देना चाहती हैं। कामकाजी ही नहीं, घरेलू महिलाएं भी बच्चों के कॅरियर की चिंता करती हैं। बच्चे पांचवी क्लास पार करते हैं तो उन्हें मांएं कुछ बनने की प्रेरणा देना शुरू कर देती हैं।

माताओं में बढ़ता आत्मविश्वास

कम पढ़ी-लिखी मांओ में भी इन दिनों गजब का आत्मविश्वास देखा जा सकता है। वे हर हाल में बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। खुद नहीं पढ़ा सकतीं तो ट्यूटर रख लेती हैं। कभी-कभार स्कूल जाकर बच्चे की प्रगति रिपोर्ट भी ले लेती हैं। परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ती। पिता बेशक सुबह बिस्तर पर सोया रहे। मगर यह मां ही है, जो बच्चे को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती हैं। उनका बस्ता ठीक करने से लेकर लंच बाक्स तक तैयार करती हैं। यहीं नहीं उन्हें स्कूल वैन तक में बैठाती हैं। कुछ मांएं तो स्कूल तक छोड़ने जाती हैं। चाहे वे रिक्शे पर ले जाएं या फिर अपनी कार में। बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए कई मांओ ने अपने कॅरियर तक की परवाह नहीं की। ऐसी कई मिसाल हैं जिनमें महिलाओं ने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया।

भारतीय माताएं सबसे सजग

दुनिया भर में भारतीय मांएं सबसे सजग हैं। उनमें लगातार बदलाव आ रहा है। अगर कोई महिला कामकाजी नहीं भी है तो भी वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए उतनी ही चिंतित हैं। वह उतनी ही व्यस्त हैं जितनी कोई कामकाजी महिला। अगर वह थोड़ी भी पढ़ी लिखी है तो वह अखबारों से न्यूज चैनलों से ज्ञान हासिल कर रही है। यहां तक कि वह इंटरनेट खंगाल कर भी बच्चों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के साथ उन्हें नवीनतम सूचनाएं दे रही हैं। वह अब दूसरों से राय नहीं लेतीं, वह सूचना तंत्र से अपनी राय खुद बना रही हैं।

अब दीन-हीन नहीं है मां

एक जमाना था कि पिता ही बच्चों के भविष्य का निर्णय करते थे। अनुशासन का डंडा उन्हीं का चलता था। पिता डाक्टर हो तो वह बच्चों को भी अपने जैसा बनाने की जिद पाल लेता था। और मांएं दरवाजे पर खड़ी सिर पर आंचल डाले चुपचाप सुनती रहती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वह हस्तक्षेप करती हैं, क्योंकि वह बच्चों की क्षमता के बारे में अपने पति से ज्यादा जानती हैं। आखिर नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक बच्चों को तैयार करने में उसकी भी कुछ भूमिका रही है। स्कूल की डायरी पढ़ने से लेकर वह होमवर्क भी तो कराती रही हैं। वह दीन-हीन कैसे हो सकती हैं? उसकी बात भी क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए। फिल्म तारे जमीन पर में वह बच्चा मुसीबत में आखिर मां को ही पुकारता है क्योंकि पिता उसकी दित तो समझता नहीं।

सहेली भी दोस्त भी

बच्चों के साथ मां का इतना गहरा रिश्ता होता है कि वह उनके बड़े होने पर बेटी की सहेली या बेटे की दोस्त जैसी हो जाती है। बेटे बताएं या न बताएं मगर बेटियां हर बात मां को बताती हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई विश्वसनीय है तो सिर्फ वही। यह एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता है जो सिर्फ मां से ही बन पाता है। भारतीय समाज के हर वर्ग में इस रिश्ते की सुगंध को आप महसूस कर सकते हैं। रिश्ते में परम्परा का बोध आज भी है मगर जीवन में आधुनिकता आने के साथ मांएं बच्चों को आंचल में छुपाए रखने की बजाय इस छांव से बाहर निकाल कर जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। इसलिए क्योंकि वह जानती हैं बेटा एक कदम भी बढ़ाएगा तो वह उसके पीछे खड़ी है। अगर गलत दिशा में गया तो भी वह उसे रोक लेगी क्योंकि वह एक सुपर मॉम है।

रिश्ते तो बहुत हैं मां सिर्फ एक है

मां की ममता को किसी परिभाषा में बांधना मुश्किल है। श्रीमती विमलेश श्रीवास्तव कहती है- दुनिया में आने के बाद बच्चा सबसे पहले मां को ही पहचानता है और उसके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द मां ही होता है।

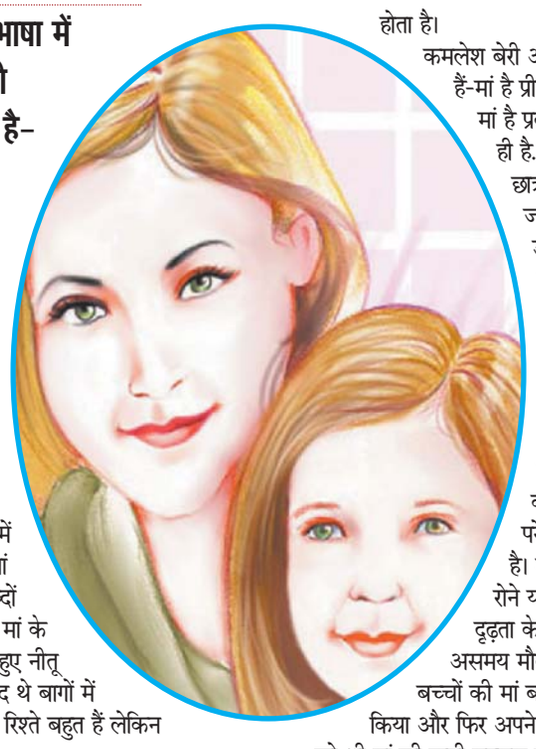

मदर्स डे पर बच्चों की भावनाएं चरम पर होती है। कोई मां के साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत कविता के रूप में बयान करता है तो किसी के लिए मां के प्रति प्यार के इजहार के लिए शब्दों की सीमा नाकाफी होती है। अपनी मां के परिश्रम और लगन की गाथा बताते हुए नीतू अग्रवाल भावुक हो उठी। उनके शब्द थे बागों में फूल बहुत हैं लेकिन गुलाब एक है, रिश्ते बहुत हैं लेकिन मां सिर्फ एक है।

प्रेमलता सरीन (योग प्रशिक्षिका) के अनुसार धरती की तरह मां भी अपने जीवन में बच्चों का सुरक्षा कवच बनती है। मां की ममता को किसी परिभाषा में बांधना मुश्किल है। श्रीमती विमलेश श्रीवास्तव कहती है-दुनिया में आने के बाद बच्चा सबसे पहले मां को ही पहचानता है और उसके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द मां ही होता है।

कमलेश बेरी अपनी अनुभूति कविताओं में व्यक्त करते हैं-मां है प्रीत, मां है मीत, नेह का सागर मां ही है, मां है प्रकाश, मां है आकाश, जीवन की भोर मां ही है...। कार्मल कान्वेंट स्कूल की नन्ही छात्रा प्रज्ञा मालवीय ने कहा,भगवान हर जगह हमारे साथ नहीं रह सकते इसलिए उन्होंने मांह के रूप में अपनी सबसे प्यारी छवि को हमारे पास भेजा है। ज्योति जोशी भावुक शब्दों में कहती है, मुझे अपनी मां का साथ जिंदगी की कड़ी धूप में शीतल छाया की तरह लगता है। मेरी हर समस्या का इलाज मेरी मां के पास है चाहे अचार डालना हो या कोई पकवान बनाना हो या फिर कोई भी व्यक्तिगत उलझन,मेरी हर परेशानी मां के पास जाकर खत्म हो जाती है। मेरी मां कहती है कि जो भी स्थिति आए रोने या कमजोर होने के बजाए उसका सामना दृढ़ता के साथ करो। आशा साहू बताती है, मैंने असमय मौत का शिकार हुई अपनी जेठानी के बच्चों की मां बनकर सर्वप्रथम मातृत्व को महसूस किया और फिर अपने बच्चों के साथ ही जेठानी के बच्चों को भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। आज मुझे बच्चों व नाती-पोतों के भरे-पूरे परिवार की सदस्य के रूप में गर्व का अहसास होता है। संध्या रामकृष्ण बायवार के शब्द कविता में कुछ यूं ढले- मां की महिमा क्या गाऊं, मां की कहानी क्या सुनाऊं, हे मां तू है महान, तूने हमको जन्म दिया, मिले हर जन्म में तेरी को,मां तुझे सलाम।

अपनी मां के परिश्रम और लगन की गाथा बताते हुए नीतू अग्रवाल भावुक हो उठीं। उनके शब्द थे बागों में फूल बहुत हैं लेकिन गुलाब एक है, रिश्ते बहुत हैं लेकिन मां सिर्फ एक है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आरसोडिया गांव के चबूतरे पर बैठ मुख्यमंत्री ने किया ग्रामीणों के साथ सहज संवाद

कम्युनिटी कोविड सेंटर का दौरा कर सुविधाओं का लिया जायजा

क्रांति समय दैनिक

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के गांवों को कोरोना मुक्त रखने और कोरोना की दूसरी लहर पर जनशक्ति के सहयोग और राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के जरिए विजय पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, वह करके और सुविधा न हो तो उसे विकसित करके भी कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीतने का प्रबल आत्मविश्वास व्यक्त किया है। शनिवार को गांधीनगर की कलोल तहसील के आरसोडिया गांव में 'मेरा गांव, कोरोना मुक्त गांव' अभियान के तहत निर्मित कोविड कम्युनिटी सेंटर के दौरे के दौरान उन्होंने कॉमन मैन (सीएम) के तौर पर ग्रामीणों के साथ गांव के चबूतरे पर बैठकर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ सहज संवाद किया और आरसोडिया गांव के संबंध में जानकारी हासिल की। कोरोना की दूसरी लहर को एक चुनौती करार देते हुए रूपाणी ने कहा कि इस तरह की महामारी शताब्दी में एक बार आती है। पिछली सदी में १९२० में स्पेनिश फ्लू नामक महामारी आई थी। उस सदी में इतनी मेडिकल सुविधाएं और डॉक्टर भी नहीं थे, बावजूद उसके उस महामारी से निपटने में मानव जाति सफल रही थी। आज कोरोना को हराने हमारे पास अनेक मेडिकल सेवाएं और दवाइयां उपलब्ध हैं, इसलिए कोरोना के विरुद्ध हमारी जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तथा बीमारी बिल्कुल नई थी इसलिए उसके सटीक निदान को लेकर डॉक्टरों में उलझन थी। लेकिन दूसरी लहर के दौरान में देश में वैक्सीनेशन जारी है तथा कोरोना की उपचार और निदान पद्धति योग्य तरीके से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमें थकना नहीं है, हारना नहीं है और न ही निराश होना है। कोरोना की पहली लहर के दौरान हमें प्रतिदिन २५० मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ने से प्रतिदिन १ हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके लिए भी राज्य सरकार ने समुचित

योजना बनाई है। राज्य के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध तरीके से हो रही है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना मरीजों की मौत हुई हो ऐसी एक भी घटना राज्य में नहीं हुई है। ४० दिनों में राज्य में ५५ हजार आईसीयू और ऑक्सीजन सुविधा युक्तबेड लगाए गए हैं। १५ मार्च, २०२१ से पहले जहां राज्य के हॉस्पिटलों में बेड की संख्या ४१ हजार थी, वहीं आज बेड की संख्या को बढ़ाकर १ लाख किया गया है। 'मेरा गांव, कोरोना मुक्त गांव' अभियान के अंतर्गत राज्य के सामुदायिक कोविड केयर सेंटरों में अतिरिक्त १ लाख बेड की सुविधा विकसित की गई है। रूपाणी ने कहा कि आज हम उस स्थिति को टालने में सफल रहे हैं जिसमें हॉस्पिटल में बेड नहीं होते थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरे देश में ताकीद की जरूरत है, इसके बावजूद एक माह में लगभग ७ लाख रेमडेसिविर की व्यवस्था कर गुजरात में कोरोना के अनेक मरीजों का जीवन बचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं भी मेडिकल स्टाफ की कमी न हो उस मकसद से डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए राज्य सरकार ने जिला कलक्टरों को शक्ति दी है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने फैबी फ्लू सहित अन्य जरूरी दवाइयों की पर्याप्त खेप राज्य के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुहैया करा दी गई है। जनता के हित में अनेक निर्णय करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग को जीतने का आत्मविश्वास लोगों को दिया है। दूसरी लहर के दौरान गत दो-तीन दिनों से कोरोना के लगातार घटते मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी लहर का सामना करने के लिए भी सरकार ने पूर्व तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने पिछले एक वर्ष से कोरोना की जंग में लगातार तैनात रहते हुए सेवा देने वाले डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवा की प्रशंसा की तथा सेवा के इस कार्य में जान गंवाने वाले अग्रिम पंक्तिके कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। शहर में कोरोना मामलों के घटने और गांवों में मामलों के बढ़ने पर चिंता व्यक्तकरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह स्पष्ट संकल्प है कि गांवों को कोरोना संक्रमण से बचाना

पश्चिम रेलवे द्वारा राष्ट्र की सेवा में ३ और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन

गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से २० टन और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली भेजी गई

क्रांति समय दैनिक

देश भर के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने के भारतीय रेलवे के प्रयासों को गति देते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा कोविड के खिलाफ संयुक्त जंग को मजबूती प्रदान करने तथा कोविड मरीजों और उनके परिवारों को राहत प्रदान के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) के परिवहन के लिए ३ और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे द्वारा ८ मई, २०२१ को दिल्ली क्षेत्र की ओर २ और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुजरात के हापा से ८ मई, २०२१ को दिल्ली कैंट के लिए ०४.४५ बजे रवाना हुई, जिसमें ६ टैंकरों के जरिये १३० टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का परिवहन किया गया। इसी प्रकार एक अन्य ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुजरात के हापा से उसी दिन दिल्ली कैंट के लिए ११.२५ बजे रवाना हुई, जिसमें ८ टैंकरों के जरिये १४४ टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का परिवहन किया गया। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए टैंकर मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज,जामनगर द्वारा उपलब्ध कराये गए हैं। यह ट्रेनें ९ मई, २०२१ की सुबह ११०५ किमी की दूरी तय करने के बाद दिल्ली कैंट पहुंचेंगी। ये टैंकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराये जायेंगे। एक अन्य ऑक्सीजन एक्सप्रेस ७ मई, २०२१ को मुंद्रा पोर्ट से २१.०० बजे दिल्ली के निकट पाटली के लिए रवाना हुई, जिसमें मेसर्स अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गए टैंकर के जरिये २० टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का परिवहन किया गया। यह

ट्रेन ८ मई,२०२१ को अपने गंतव्य पर पहुँच गयी। ठाकुर ने बताया कि पश्चिम रेलवे ने अब तक १२ आक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिये लगभग १०२९ टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (LMO) का परिवहन किया है। इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर क्रायोजेनिक कार्गो के कारण सभी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए लगभग ५३-५६ किमी प्रति घंटे की औसत गति से निर्बाध पथ पर चलाया गया, ताकि इन्हें कम से कम समय में और जल्द से जल्द गंतव्य स्थलों

सार-समाचार

कोरोना से पुत्र की मौत पर परिजनों की अस्पताल में तोडफोड

पाटन,पाटपापाशहरी सबरीमाला कोविड अस्पाताल के आईसीयु वोर्ड में दाखिल युवक की कोरोना से मौत पर युवक के परिजनों ने अस्पताल पर पुत्र की खबर नहीं देने और पैसे भरने के बाद शव नहीं देना का आरोप लगाते हुए हंगामा कर तोडफोड की।

पाटन के सिद्धपुर में निजी अस्पताल सबरीमाला में बनासकांठा के मोटा जामपुर गांव कोरोना से संक्रमित सहदेवजी वणझारा को गंभीर हालत में आईसीयू वार्ड में दाखिल किया गया था। युवक की हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत में युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के को लेकर परिजनों ने अस्पताल के आईसीयू वार्ड में तोडफोड कर हंगामा मचाया। घटना को लेकर अस्पताल संचालक ने पुलिस को सूचना पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मामला शांत किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मरिज के बडे भाई भरतसिंह वणझारा ने बताया कि मेरे छोटे ३ बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल संचालकों को एक लाख रुपए एडवांस दिया था। मुझे आशंका होने पर मैंने आईसीयू में जाकर देखा तो मेरा भाई मृत था। मैंने अस्पताल संचालक से कहा कि हमें सूचना क्यों नहीं अस्पताल संचालकों ने कहा कि एक लाख रुपए की मांग की और बाद में शव देने को कहा। अस्पताल के मालिक एम.के.पटेल ने कहा कि मरिज की हालत नाजुक थी। युवक को गंभीर हालत में देखते हुए उसकी मौत की जिम्मदारी हमारी नहीं रहेगी का लिखित रिपोर्ट के बाद मरिज को भर्ती किया था। हमने शव देने को मना नहीं किया। युवक की मौत पर मृतक के परिजनों ने तोडफोड कर स्टाफ के साथ मारपीट की। इस घटना से अन्य गंभी मरिजों को भी हेरानगति हुई। हम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे।

विवाहिता से नाजायज संबंध पड़ा महंगा, बेटे ने मां के प्रेमी को उतारा मौत के घाट

देवभूमि द्वारका,जिले के देवलिया गांव से एक युवक की लहूलुहान हालत में लाश मिली थी। पुलिस चंद घंटों में मामले की गुत्थी सुलझाते हुए युवक की हत्या के आरोपी फरार हो उससे पहले ही उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में हत्या की वजह सुनकर पुलिस भी चौंक गई। देवभूमि द्वारका जिले की कल्याणपुर तहसील के देवलिया गांव निवासी ३६ वर्षीय छगन वरूनामक युवक के उसी गांव में रहनेवाली एक विवाहित महिला के साथ नाजायज संबंध थे।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सांद्रकों की जमाखोरी का मामला अपराध शाखा को सौंपा

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सांद्रक की कथित तौर पर जमाखोरी और काला बाजारी करने का मामला अपराध शाखा को सौंप दिया है। इस मामले में अपराध शाखा ने 500 से अधिक मशीनों को बरामद किया था। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने शुक्रवार को खान मार्केट इलाके में दो रेस्त्रां में छापे मारकर 105 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए थे। साथ ही उसने बृहस्पतिवार को दक्षिण दिल्ली में एक रेस्त्रां तथा एक फार्म हाउस में छापे मारकर 419 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए थे और चार लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 524 ऑक्सीजन सांद्रकों की कथित जमाखोरी का मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, ''खान मार्केट में दो रेस्त्रां खाना चाचा और टाउन हॉल से 105 ऑक्सीजन सांद्रक जब्त करने के साथ ही काला बाजारी करने वाले नवनीत कालरा से 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए। दयाल ऑप्टिकल्स का मालिक कालरा फरार है। दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी जिले से प्रबंधक और तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। और छापे मारे जा रहे हैं।'' पुलिस ने बताया कि नवनीत कालरा तीन रेस्त्रां का मालिक है। उसका मोबाइल फोन बंद है और वह फरार है। एक निजी कंपनी ने चीन से इन ऑक्सीजन सांद्रकों का आयात किया था।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने चुनाव के बाद हिंसा को लेकर मुख्य सचिव को किया तलब

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को शनिवार शाम तक उनसे मुलाकात करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के गृह सचिव ने उन्हें चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी कानून-व्यवस्था की स्थिति से अवगत नहीं कराया। धनखड़ ने ट्वीट किया कि गृह सचिव ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कोलकाता पुलिस आयुक्त की इस संबंधी रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ''मुख्य सचिव को आज शाम सात बजे से पहले मुझसे मुलाकात करने को कहा गया है, क्योंकि गृह विभाग के एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) ने चुनाव के बाद हिंसा के संबंध में कानून एवं व्यवस्था पर स्थिति रिपोर्ट पेश नहीं की।' उन्होंने कहा, ''संवैधानिक व्यवस्थाओं से (मुख्यमंत्री) ममता (बनर्जी) के प्रशासन का दूर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।'' धनखड़ ने लिखा, ''राज्य चुनाव के बाद हिंसा की सबसे गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख को कोई जानकारी नहीं दी गई। इसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी।'' पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई है।

लोगों से दिल्ली से न जाने की अपील करना अरविंद केजरीवाल का नाटक है: मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान को ''नाटक'' बताया है, जिसमें उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय राजधानी से पलायन नहीं करने की अपील की थी। मायावती ने गरीबों, दलितों एवं आदिवासी समुदायों के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण किए जाने की मांग की। बसपा नेता ट्वीट किया, '' दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि दिल्ली के लोग पलायन न करें। उन्होंने यही नाटक कोरोना वायरस के दौरान पहले भी किया था। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में भी अब यही देखने को मिल रहा है। अब पंजाब के लुधियाना से भी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। यह अति-दुःखद है।'' उन्होंने कहा, ''यदि इन जगहों की राज्य सरकारें इन लोगों में विश्वास पैदा करके उनकी जरूरतों को समय से पूरा कर देतीं तो ये लोग पलायन नहीं करते। ये राज्य सरकारें इस मामले में अपनी कमियों को छिपाने के लिए अलग-अलग तरह की नाटकबाजी कर रही हैं। यह किसी से छिपा नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने मांग की कि पूरे देश में खासकर गरीबों, दलितों एवं आदिवासी समुदायों के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाना चाहिए और उनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए।

कोविड-19: जेलों में भीड़ कम करने के लिये कोर्ट ने कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया

नयी दिल्ली। देश में कोविड-19 के मामलों में 'अभूतपूर्व वृद्धि' पर संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को जेलों में भीड़ कम करने का निर्देश देते हुए कहा कि जिन कैदियों को पिछले साल महामारी के मद्देनजर जमानत या पैरोल दी गई थी उन सभी को फिर वह सुविधा दी जाए। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की एक पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बनाई गई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा पिछले साल मार्च में जिन कैदियों को जमानत की मंजूरी दी गई थी, उन सभी को समितियों द्वारा पुनर्विचार के बगैर पुनः वह राहत दी जाए, जिससे विलंब से बचा जा सके। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर शनिवार को अपलोड हुए आदेश में कहा गया, फइसके अलावा हम निर्देश देते हैं कि जिन कैदियों को हमारे पूर्व के आदेशों पर पैरोल दी गई थी उन्हें भी महामारी पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत फिर से 90 दिनों की अवधि के लिये पैरोल दी जाए।फ एक फैसले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से कहा कि उन मामलों में यांत्रिक रूप से गिरफ्तारी से बचें जिनमें अधिकतम सजा सात वर्ष की अवधि की है। पीठ ने उच्चाधिकार प्राप्त समितियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों को अपनाते हुए नए कैदियों की रिहाई पर विचार करें।

शिवसेना ने सेंट्रल विस्टा परियोजना पर भाजपा पर साधा निशाना

मुंबई। (एजेंसी)।

शिवसेना ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 से निपटने में जहां पड़ोस के छोटे देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं वहीं मोदी सरकार कई करोड़ के सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को रोकने के लिए भी तैयार नहीं है। पार्टी ने यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा पिछले 70 वर्ष में बनाई गई व्यवस्था ने देश को कठिन समय से पार पाने में मदद की है जिसका सामना वह आज कर रहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' के एक संपादकीय में कहा, 'यूनिसेफ ने डर व्यक्त किया है कि भारत में जिस गति से कोरोना वायरस फैल रहा है उससे दुनिया को वायरस से खतरा है। इसने यह भी अपील की है कि अधिकतम देशों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश ने रेमडेसिविर की 10,000 शीशियां भेजी हैं जबकि भूटान ने चिकित्सीय ऑक्सीजन। नेपाल, म्यांमा और श्रीलंका ने भी 'आत्मनिर्भर' भारत की मदद की पेशकश की है।'

इसमें कहा गया, 'साफ तौर पर, भारत नेहरू-गांधी द्वारा बनाई गई व्यवस्था के सहारे है। कई गरीब देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं। इससे पहले, पाकिस्तान, रवांडा और कॉन्गो जैसे देश दूसरों से मदद लेते थे। लेकिन आज के शासकों की गलत नीतियों के चलते, भारत आज इस स्थिति से गुजर रहा है।' शिवसेना ने कहा कि जहां गरीब देश अपने-अपने तरीके से भारत की मदद कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ रुपये की महत्वकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोकने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि किसी को भी इस बात का अफसोस नहीं है कि एक तरफ भारत बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों से मदद ले रहा है वहीं दूसरी तरफ मोदी नये संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए कई करोड़ की सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने को तैयार नहीं हैं।

शिवसेना ने कहा कि दुनिया कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर से जूझ रही है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर और खतरनाक होगी। लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा को आज भी बस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे भी घेरने की पड़ी है। इसने कहा कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यिन स्वामी ने स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को देने की मांग की है और यह इस बात का सबूत है कि मौजूदा स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह विफल रहा है।

कोविड-19 के उपचार में विदेशी दवाओं पर ज्यादा निर्भरता से बचें: बंबई उच्च न्यायालय

मुंबई। (एजेंसी)।

आयातित दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता से बचने की सलाह देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वे विदेशी उत्पादकों की दवाओं जैसे- टोसिलीजुमैब, के उचित विकल्प के बारे में जागरूकता पैदा करने को कहा है, जिनका इस्तेमाल कोविड-19 के उपचार में किया जा सकता है। मख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की एक पीठ ने कहा कि टोसिलीजुमैब की कमी को देखते हुए, सरकार को नागरिकों को यह बताना चाहिए कि इसके बजाए कौन सी अन्य स्थानीय स्तर पर उत्पादित, सस्ती और व्यापक रूप से उपलब्ध दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा, 'भारत सरकार ने ऑन रिकॉर्ड यह मत व्यक्त किया है कि इटोलीजुमैब, डेकसामेथासोन और मिथाइलप्रेडनीसोलोन दवाएं टोसिलीजुमैब के समकक्ष हैं और/या बेहतर हैं और यह उचित समय है कि उसके और राज्य सरकार द्वारा जनता की यह गलत धारणा बदलने का प्रयास किया जाए कि सिर्फ टोसिलीजुमैब से ही कोविड-19 के मरीजों को आराम मिल सकता है।' अदालत ने कहा, 'आयातित दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जाना चाहिए और सभी संबंधितों को अवगत कराया जाना चाहिए कि वे उपचार कर रोगियों को ठीक करें तथा जीवन रक्षक दवाओं से लाभ न कमाएं।' उच्च न्यायालय ने यह आदेश छह मई को पारित किया था लेकिन उसकी वेबसाइट पर यह शुक्रवार रात को उपलब्ध कराया गया।

पश्चिम बंगाल में हुई राज्यव्यापी हिंसा पूर्व नियोजित और लोकतंत्र के खिलाफ: आरएसएस

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद राज्य में अनियंत्रित तरीके से हुई राज्यव्यापी हिंसा न केवल निंदनीय है, बल्कि पूर्व नियोजित भी है तथा लोकतंत्र की मूल भावना के भी विपरीत है। पश्चिम बंगाल में दो मई को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हिंसा की अनेक घटनाओं की खबरें आई हैं। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा का आरोप लगाया है और कहा है कि इन हिंसक घटनाओं में उसके कई कार्यकर्ता मारे गए और कई घायल हुए।

राज्य में चुनाव में ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत हासिल हुई, जबकि भाजपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अपने बयान में कहा कि बंगाल में असामाजिक शक्तियों ने महिलाओं के साथ घृणास्पद बर्बर व्यवहार किया, निर्दोष लोगों की क्रूरतापूर्ण हत्याएँ कीं, घरों को जलाया। उन्होंने दावा किया कि इन घटनाओं में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों-दुकानों को लूटा एवं हिंसा के फलस्वरूप अनुसूचित जाति-जनजाति समाज के बंधुओं सहित हज़ारों लोग अपने घरों से बेघर होकर प्राण-मान रक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों पर शरण के लिए मजबूर हुए हैं। आरएसएस के सरकार्यवाह ने आरोप लगाया कि इस पाशविक हिंसा का सर्वाधिक दुखद पक्ष यह है कि शासन और प्रशासन की भूमिका केवल मूक दर्शक की ही दिखाई दे रही है। दंगाइयों को ना ही कोई डर दिखाई दे रहा है और ना ही शासन-प्रशासन की ओर से नियंत्रण की कोई प्रभावी पहल दिखाई दे रही है। होसबाले ने कहा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद उन्मुक्त होकर अनियंत्रित तरीके से हुई राज्यव्यापी हिंसा न केवल निंदनीय है, बल्कि पूर्व नियोजित भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव को दल जीतते हैं, पर निर्वाचित सरकार पूरे समाज के प्रति जवाबदेह होती है। उन्होंने कहा, '' हम नव निर्वाचित सरकार से यह आग्रह करते हैं कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में चल रही हिंसा को तुरंत समाप्त कर क़ानून का शासन स्थापित करना, दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना, हिंसा-पीड़ितों के मन में विश्वास और सुरक्षा का भाव पैदा करना होना चाहिए।'' आरएसएस के सरकार्यवाह ने कहा, ''हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करते है कि वह बंगाल में शान्ति क़ायम करने हेतु आवश्यक हर सम्भव कदम उठाएँ एवं यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार भी इसी दिशा में कार्रवाई करें।'' होसबाले ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के सभी प्रबुद्ध जनों, सामाजिक-धार्मिक-राजनैतिक नेतृत्व का भी आहवान करता है कि इस संकट की घड़ी में वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होकर विश्वास का वातावरण बनायें, हिंसा की कठोर शब्दों में निंदा करें एवं समाज में सद्भाव और शांति व भाईचारे का वातावरण खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायें।

केंद्र ने पिछले छह महीने में कोई काम नहीं किया, सत्ता के लिए रोजाना बंगाल आए मंत्री: ममता बनर्जी

कोलकाता। (एजेंसी)।

लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा पर हमलावर हैं। आज एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के इरादे से मंत्री हर रोज बंगाल आते रहे।

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग को तत्काल सुधार की आवश्यकता है। बंगाल में एक रीढ़ है और यह कभी नहीं झुकती है। एक साजिश थी, सभी केंद्रीय मंत्री यहां उतरे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने विमानों और होटलों पर कितने करोड़ रुपये खर्च किए। यहां पानी की तरह बह रहा था पैसा। ममता ने कहा कि बंगाल के साथ इतना भेदभाव क्यों है? उन्होंने शपथग्रहण के 24 घंटे के भीतर केंद्रीय टीम भेजी। दरअसल, वे (भाजपा) जनता के जनादेश को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता। वे फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैला रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने हमलावर रुख को जारी रखते हुए आरोप लगाया कि सभी का टीकाकरण केंद्र की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन वह नए संसद भवन, प्रधानमंत्री के आवास आदि पर 50000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ममता बनर्जी ने यह बातें विधानसभा में कहीं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड-19 के उपचार के लिए चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है। ममता ने यह भी कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में कुल उत्पादन में से अन्य राज्यों के लिए ऑक्सीजन आवंटन में पश्चिम बंगाल की जरूरत बढ़ने के बावजूद बढ़ोतरी की।

कोरोना की दवा को मंजूरी, डीआरडीओ की मेडिसिन से कम होगी ऑक्सीजन की जरूरत

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

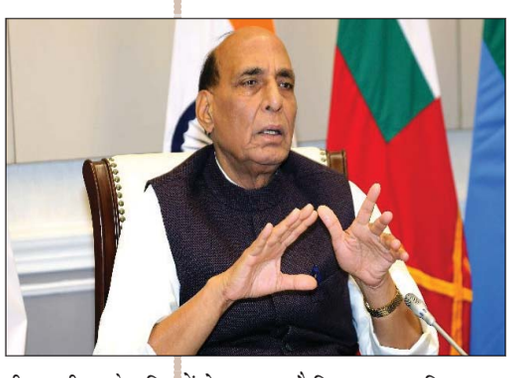

भारत के औषधि महानियंत्रक ने डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविडरोधी दवा को आपात इस्तेमाल के लिये मंजूरी दी। कोविड रोधी दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) डीआरडीओ द्वारा हैदराबाद स्थित डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मिलकर विकसित की गई है।

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने गंभीर कोविड -19 रोगियों के लिए एक सहायक चिकित्सा के रूप में दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज , डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन की एक लैब ने डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, हैदराबाद के साथ मिलकर दवा विकसित की है। नैदानिक परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि यह अणु अस्पताल में भर्ती मरीजों की तेजी से रिकवरी में मदद करता है और पूरक ऑक्सीजन निर्भरता को कम करता है। एक सामान्य अणु और ग्लूकोज के एनालॉग होने के नाते, इसे आसानी से उत्पादित और भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है। डीआरडीओ ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा 2-डीजी के साथ इलाज किए गए रोगियों के उच्च अनुपात ने कोविड रोगियों में आरटी-पीसीआर नकारात्मक रूपांतरण दिखाया। अप्रैल 2020 में, कोविड -19 की पहली लहर के दौरान, INMAS-DRDO के वैज्ञानिकों ने सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी , हैदराबाद की मदद से प्रयोगशाला प्रयोग किए और पाया कि यह अणु SARS-CoV-2 वायरस के लिए प्रभावी रूप से काम करता है और वायरल विकास को रोकता है। इन परिणामों के आधार पर डीसीजीआई सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने मई 2020 में कोविड -19 रोगियों में 2-डीजी के चरण-द्वितीय नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा- दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक नहीं मिली

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस और दिल्ली में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर एक कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल ने कहा यदि दिल्ली सरकार को प्रति माह कोविड़-19 वैक्सीन की 80-85 लाख खुराक दी जाती है, तो हम तीन महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा यदि हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक मिलती है, तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। दिल्ली में 18 वर्ष से ऊपर के 1.5 करोड़ लोग हैं इसलिए हमें 3 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। इसमें से दिल्ली सरकार को अब तक केवल 40 लाख खुराक मिली है। हमें 2.6 करोड़ और खुराक चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि निकट भविष्य में 300 और स्कूलों में कोविड -19 टीकाकरण केंद्र होंगे। दिल्ली ने एक टीकाकरण अभियान शुरू किया है और युवा प्रणाली से खुश हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर दिन लगभग 1 लाख टीके लगाए जा रहे हैं और कई लोग नोएडा, गाजियाबाद से टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगले पांच-छह दिनों के लिए टीके हैं और उन्होंने केंद्र से पर्याप्त टीके उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर दिन एक लाख टीके लग रहे हैं और यह संख्या तीन लाख तक बढ़ सकती है। कोविड-19 की तीसरी लहर की चेतावनियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए टीका ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने केंद्र और विशेषज्ञों से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी टीका लगाने के विकल्प तलाशने का भी अनुरोध किया।

सर्बानंद सोनोवाल या हिमंत बिस्व सरमा? बीजेपी आज कर सकती है असम के नए मुख्यमंत्री की घोषणा

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

असम में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल दोबोरा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर हिमंत बिस्व सरमा को पार्टी मौका दे सकती है, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। आज दोनों ही नेताओं को दिल्ली तलब किया था, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बैठक हुई। दिल्ली छोड़ने से पहले आज हिमंस बिस्व सरमा ने कहा कि कल गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इस बैठक के बाद सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगा।

सोनोवाल, सरमा ने नड्डा, शाह से की दिल्ली में मुलाकात: असम के नए मुख्यमंत्री को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच, राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत बिस्व सरमा ने पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यहां शनिवार को मुलाकात की। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने असम में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को असम के निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल एवं स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेता शनिवार सुबह दिल्ली पहुंच गए, लेकिन पहले सरमा नड्डा और भाजपा महासचिव (संगठन) बी एल संतोष से मुलाकात करने नड्डा के आवास पहुंचे। बाद में शाह भी वहां पहुंचे। सरमा के जाने के बाद सोनोवाल ने भी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इन बैठकों में इस बात पर भी मुख्य रूप से वार्ता हुई कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बैठकों में असम में अगली सरकार के गठन को लेकर चर्चा की गई।

सरमा मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार: असम के सोनोवाल-कचहरी आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाले सोनोवाल और उत्तर पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक सरमा मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं। भाजपा ने असम में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। पार्टी ने 2016 विधानसभा चुनाव में सोनोवाल को इस पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था और चुनाव जीता था। इसी के साथ पूर्वोत्तर में भगवा दल की पहली सरकार गठित हुई थी। इस बार,पार्टी ने कहा था कि वह चुनाव के बाद फैसला करेगी कि असम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।

लॉकडाउन की जरूरत अब अधिक, केंद्र सरकार करे फैसला: अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन को जरूरी बताते हुए शनिवार को कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार के स्तर पर होना चाहिए। गहलोत ने यहां एक बयान में कहा, 'संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की पहले से अधिक आवश्यकता अभी है। मेरी राय है कि पिछले अनुभव के आधार पर ये फैसला केन्द्र सरकार के स्तर पर होना चाहिए जिससे मजदूरों सहित आम लोगों को कम से कम तकलीफ हो एवं साथ में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। ' उन्होंने कहा, 'आज तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई राज्य एक के बाद एक लॉकडाउन लगाते जा रहे हैं। कई राज्य दूसरे राज्यों के नागरिकों का प्रवेश बंद कर रहे हैं। हमने भी राज्य में सोमवार से सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। यह देखा गया है कि इस बार ग्रामीण इलाकों एवं युवाओं में कोरोना वायरस संक्रमण तेज गति से फैल रहा है। संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने के लिए राज्य भर में सोमवार से सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपना नागरिक धर्म निभाएं और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें जिससे राजस्थान को कोरोना सक्रमण से बचाया जा सके। गहलोत ने कहा कि लोगों के सहयोग से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है और जनता अगर इसी तरह साथ देगी तो जल्द से जल्द कोरोना पर विजय प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए राज्य में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है। इस दौरान कोई विवाह समारोह नहीं होगा और सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्य भी इस दौरान स्थगित रहेंगे।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफ़सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)